● वर्ष-6
● अंक-93
रायपुर, रविवार
15 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> बच्चे में इस डर को दूर करने...



भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप: मोहित-मनल ने पाकिस्तान के जबड़े से छीनी जीत

अल अमीरात। अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय युवा टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को बेहद रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने 338 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 337 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने शानदार शतक जड़ते हुए 107 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं अब्दुल कादिर ने 80 रनों का अहम योगदान दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में काव्य परेश पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि सी. वेंकट को 3 सफलताएं मिलीं। 338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मुकाबले में संघर्ष जारी रखा। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए। वहीं आर्यवीर सहवाग ने 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली।

प्रदेश में आज से शुरु होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

रायपुर। प्रदेश में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ रविवार 15 नवंबर से प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता,



इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस साल 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे को और मजबूत करते हुए हमने तय किया है कि यदि कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के अंतर की राशि दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 13,839 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

गोधरा कांडः मुस्लिम अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका

नई दिल्ली। साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने शनिवार को दावा किया कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने जांच के लिए उन्हें मुस्लिम पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए थे। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अस्थाना ने कहा कि जांच के दौरान उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था। राकेश अस्थाना ने कहा, %मैं यह बताना चाहूंगा कि शुरुआती जांच में मैंने देखा कि जिस इलाके में यह घटना हुई थी, वहां पूरी तरह मुस्लिम आबादी रहती थी। ऐसे में मुस्लिम इलाके में जांच करने के लिए व्यावहारिक और पेशेवर तौर पर मुस्लिम अधिकारियों की जरूरत थी। मैंने उनसे जांच टीम में शामिल करने के लिए कुछ मुस्लिम अधिकारी देने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों ने जांच में बेहद अहम भूमिका निभाई। अस्थाना ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि दो मुस्लिम कांस्टेबल करीब डेढ़ महीने तक गुप्त रूप से चूड़ियां और साड़ियां बेचने वाले बनकर रहे।



सरकार ने दी थी पूरी छूट

राकेश अस्थाना ने कहा कि उन्हें अपनी पसंद के वकील चुनने और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए सबसे महंगे वकील को नियुक्त करने तक की छूट थी। अस्थाना के मुताबिक, आरोपपत्र दाखिल करने जितना ही जरूरी अदालत में आरोपियों को दोषी साबित करना भी था। अस्थाना ने कहा कि अगर जांच में जुटाए गए सबूत मजबूत नहीं होते, तो अदालतें पुलिस की जांच में खामियां निकालतीं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसलों से साबित होता है कि जांच में कोई दखल नहीं दिया गया और पूरी निष्पक्षता बरती गई। गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 2011 में एक विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था।

एमपी के मंदिरों और स्मारकों से गायब हो चुकी हैं 142 बेशकीमती मूर्तियां



भोपाल। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों से बेशकीमती धरोहरों के चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में शिवपुरी के नरवर फोर्ट से 3.5 टन भारी प्राचीन तोप गायब होने की सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों से जितनी प्राचीन मूर्तियां और एंटीक चीजें चोरी हुई हैं, उनमें से करीब एक तिहाई यानी 142 अकेले मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 1961 से 2024 के बीच देश भर के एएसआई संरक्षित स्थलों से लगभग 488 प्राचीन वस्तुएं चोरी हुई हैं।

खालिस्तान की आग भड़काने की तैयारी में आईएसआई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सिख प्रवासियों और कश्मीर से जुड़े दबाव समूहों को एकजुट करने के लिए एक साल की योजना तैयार की है। विदेशों में मौजूद अपने संपर्कों के जरिए पाकिस्तान की इस कवायद पर भारतीय एजेंसियों की नजर है। इस्लामाबाद भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है। इसके लिए उसने विदेशों में सक्रिय अपने लोगों पर भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। अगले एक साल में पाकिस्तान का मुख्य फोकस अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को पाकिस्तान बुलाने पर होगा।



राष्ट्रपति मुर्मु से राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की शिष्टाचार भेंट

नई दिल्ली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह तथा देश के अन्य प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने 11 नवम्बर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की।

135 प्रशिक्षु आईपीएस से गृह मंत्री अमित शाह का संवाद; राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर चर्चा

नई दिल्लीा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 78वें नियमित भर्ती बैच (आरआर) के 135 प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। अमित शाह ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के साथ मौजूदा समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, आदि मुद्दों पर चर्चा की। 78वें नियमित भर्ती बैच का बुनियादी प्रशिक्षण 8 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 17 अक्टूबर 2026 को चरण-द्व प्रशिक्षण का समापन पासिंग आउट परेड के साथ हुआ।



गृह मंत्री अमित शाह के साथ यह संवाद प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक अवसर रहा। इस अवसर ने भावी पुलिस नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन तथा जनसेवा के क्षेत्र में अपनी भावी जिम्मेदारियों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने का विशिष्ट मंच प्रदान किया।

यह संवाद प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों में कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीधा संवाद किया। वर्तमान समय की पुलिसिंग को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, पुलिस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से परे भी अनेकों चुनौतियां हैं, इन विषयों पर सवाल जवाब हुए। साइबर क्राइम और ड्रग्स को कैसे खत्म किया जाए, इनके पीछे का आर्थिक तंत्र कैसे काम करता है>

प्रमुख समाचार
राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

धरमजयगढ़ में आज जनजातीय गौरव सम्मेलन, नितिन नबीन होंगे शामिल

रयापुर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। दशहरा मैदान में सुबह 10-30 बजे से आयोजित होने वाले इस



सम्मेलन में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक संघर्ष, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को रेखांकित किया जाएगा। में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान देने के उद्देश्य से की थी। इसके माध्यम से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देने की पहल की गई। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर उलगुलान का नेतृत्व किया था। उनका संघर्ष आदिवासी स्वाभिमान, अधिकारों और स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक बन गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों की भूमिका को सामने लाने में उनका योगदान विशेष महत्व रखता है।

डोडा में चार घंटे के भीतर भूकंप के तीन झटके, 3.8 रही तीव्रता



जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को चार घंटे के भीतर तीन बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों भूकंपों के केंद्र लगभग पूर्व-पश्चिम दिशा में एक सीधी रेखा में रहे हैं। इनके बीच का कुल क्षेत्र करीब 11.5 किलोमीटर तक फैला है।

तीनों भूकंप महज चार घंटे 38 मिनट के भीतर दर्ज किए गए। इनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर क्रमशः 2.7, 3.8 और 2.9 रही। भूकंप के केंद्र जमीन से पांच से दस किलोमीटर की गहराई में दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे तेज 3.8 तीव्रता का भूकंप महज पांच किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप के केंद्रों का सीमित भौगोलिक दायरे में लगभग एक सीध में होना खास बनाता है। डोडा-किश्तवाड़ क्षेत्र पहले से ही भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील और जटिल संरचना वाला इलाका माना जाता है। इस क्षेत्र में वर्ष 2013 में 5.7 तीव्रता का किश्तवाड़ और वर्ष 2023 में 5.4 तीव्रता का भूकंप डोडा में आ चुका है।

सड़क हादसे में 3 की मौत

बागबाहरा। बागबाहरा में शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 3 अन्य लोग घायल हो गए है। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 04 एनएच 7746 रोड में खड़ी ट्रक क्रमांक सीजी 06 जीआर 8455 से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और पूरी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे पलट गई। गाड़ी के शीशे टूटकर दूर तक बिखर गए और वाहन का गला हिस्सा पूरी तरह दब गया।



बोलेरो में सवार सभी लोग बलांगीर जिला उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वाहन में कल्याणी 50 वर्ष, बारिहा प्रधान, लख्मी, प्रशांतो और उतरा सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक अन्य घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को 108 एंबुलेंस से बागबाहरा के अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी में डॉ गिरधारी दीवान थे। उन्होंने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।

महादेव बेटिंग: छह राज्यों में 33 जगहों पर छापेमारी



रायपुर। महादेव बेटिंग एप का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। इसके बाद महादेव सट्टेबाजी एप मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते कुछ दिनों में छह राज्यों में पैनल ऑपरेटर्स के 33 जगहों पर रेड मारी है। जांच एजेंसी के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में पिछले दिनों छह राज्यों में पैनल ऑपरेटर्स के 33 ठिकानों पर छापेमारी कर ऑपरेटरों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। इस छापेमारी के दौरान कई जगह लाइव सट्टा और जुए के पैनल मिले हैं, जिसे सीबीआई ने बंद करवाया। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इससे जानकारी मिली है कि दूसरे लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर सट्टे की रकम जमा की जाती थी और हवाला के जरिये विदेशों में पैसे भेजे जाते थे। यह कार्रवाई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई। उसे 1 नवंबर 2026 को ओमान से भारत लाया गया था।

दुनिया में 25.2 करोड़ मरीज अपनी बीमारी से अनजान



नई दिल्ली। भारत में 3.86 करोड़ लोगों को पता ही नहीं कि वे डायबिटीज की चपेट में हैं। ये लोग बिना जानकारी के बीमारी के साथ जी रहे हैं और इलाज से दूर हैं। चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि देश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि यह बीमारी देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डाल रही है। एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक, 2020 से 2050 के बीच डायबिटीज के कारण भारत को करीब 11.4 ट्रिलियन डॉलर (1,074.56 लाख करोड़ रुपये) का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस आकलन में इलाज और कामकाज पर बीमारी के असर के साथ मरीजों की देखभाल में परिवार के सदस्यों के लगने वाले समय और उनकी कमाई का नुकसान भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन (आईडीएफ) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 20 से 79 वर्ष की उम्र के करीब 8.98 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इनमें 3.86 करोड़ लोगों को अपनी बीमारी की जानकारी नहीं है। यानी देश में डायबिटीज के हर 100 मरीजों में करीब 43 ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। दुनिया की स्थिति भी इससे अलग नहीं है।

राहुल विदेशी ताकतों की कठपुतली, दूसरे देशों की मदद से चाहते सत्ता परिवर्तन

रेनू तिवारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट-2026' में 'भारत-विरोधी ताकतों' को आमंत्रित करने का शनिवार को आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीति अब राजनीतिक विरोध की सीमाएं पार कर

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित भारत समिट-2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शनिवार को भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस शिखर सम्मेलन में ऐसे विदेशी और अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिनके तार कथित तौर पर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस समर्थित नेटवर्कों से जुड़े हैं और जिनका भारत-विरोधी बयान देने का इतिहास रहा है। सत्तारूढ़ दल ने सवाल उठाया कि क्या यह सम्मेलन वास्तव में वैश्विक संवाद का मंच है, या फिर भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विमर्श (नैरेटिव) गढ़ने का एक नया अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। वहीं, कांग्रेस का पक्ष है कि इस आयोजन का उद्देश्य नई वैश्विक व्यवस्था, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 70 देशों के विशेषज्ञों के साथ रचनात्मक चर्चा करना है।



केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने सवाल किया कि क्या यह शिखर सम्मेलन संवाद का एक मंच है, या फिर ''भारत-विरोधी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया कराने की कोशिश'' है। भाजपा ने इक्काडोर के पूर्व विदेश मंत्री गुइल्युम लॉन्ग और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी समेत कुछ अन्य लोगों को 'भारत समिट 2026' में वक्ताओं की सूची में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए। इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किया है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब राजनीतिक विरोध की सीमाओं को पार करती हुई और ''राष्ट्र-विरोधी रास्ते'' की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है।

इसे भी पढ़ें- हैदराबाद में राहुल गांधी का तीखा प्रहार- %2014 में खत्म हो गया था लोकतंत्र%; महाराष्ट्र चुनाव और %वोट चोरी% के आरोपों के साथ क्लिक पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, ''जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है, भारतीय लोकतंत्र को लेकर संदेह जताता है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो राहुल गांधी के चेहरे पर खुशी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है।'' अग्रवाल ने कहा, ''जब भारत पर आरोप लगते हैं तो वह खुश क्यों होते हैं जबकि देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो वह चुप क्यों रहते है?'' भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया, और अब वे विदेशियों को भारत बुलाकर उन्हीं जैसे आरोप लगवा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, ''क्या भारत की छवि खराब करना ही राहुल गांधी की राजनीति का एकमात्र एजेंडा बन गया है?''

अग्रवाल ने कहा, ''राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'' अग्रवाल ने इससे पहले दिन में कहा था कि कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि हैदराबाद में अपने 'भारत समिट 2026' में गुइल्युम लॉन्ग को आमंत्रित करने के पीछे उसका क्या एजेंडा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट में कहा, 'लॉन्ग सीईपीआर संस्था में वरिष्ठ शोधार्थी हैं। बताया जाता है कि सीईपीआर को 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित 'ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर' से 4,20,000 डॉलर का अनुदान मिला था।'' अग्रवाल ने मार्च 2025 में बेंगलुरु के आठ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई तलाशी का भी जिक्र किया। यह कार्रवाई 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' और उसके लाभार्थियों से कथित तौर पर जुड़ी थी, और इसका संबंध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन से बताया गया है।





श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

जनजातीय गौरव दिवस

मुख्य अतिथि

श्री नितिन नवीन

माननीय राज्यसभा सांसद

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शत् शत् नमन

15 नवंबर 2026

समय - प्रातः 9 बजे

दशहरा मैदान, धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

समावेशी विकास एवं उत्थान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से **6,691** गांवों के **11 लाख** से अधिक परिवार और पीएम-जनमन से **1,544** गांवों के **56,569** परिवार लाभान्वित

संस्कृति और विरासत का संरक्षण

₹50 करोड़ की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण



महिला सशक्तीकरण

19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाओं को **₹629.64** करोड़ अंतरित मिल रहा **महतारी वंदन योजना** का लाभ

सुरक्षित भविष्य की आधारशिला

75 एकलव्य और **14 प्रयास** आवासीय विद्यालय संचालित, **34 हजार** से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित

सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन

9.86 लाख जनजातीय परिवारों को **पक्के आवास**

वन अधिकारों से सशक्तीकरण

4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत, **46,868** सामुदायिक और **4,412** सामुदायिक वन संसाधन **अधिकार पत्र वितरित**

समृद्धि । सम्मान । सर्वांगीण विकास

संवाद-49787/154

डीआरजी सर्च अभियान में बड़ी सफलता डुंगा रेकावाया के जंगल से नक्सल डंप बरामद



नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से मुक्ति की घोषणा के बाद भी नारायणपुर जिले के अंदरूनी और जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है।इसी कड़ी में डीआरजी की टीम ने ग्राम डुंगा एवं रेकावाया के जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर बड़ी संख्या में नक्सलियों के इस्तेमाल की गई मशीनरी उपकरण और तकनीकी सामग्री बरामद की है।

बरामद सामग्री में दो ड्रिल मशीन, दो वेल्डिंग मशीन, एक कटर मशीन, तीन ब्लोअर, एक बेंच ग्राइंडर, एक टेबल ड्रिल मशीन और दो टेबल ग्राइंडर शामिल हैं। इसके अलावा ड्रिल मशीन में उपयोग होने वाला एक मोटर, आर। बॉक्स वायर, स्प्रिंग वायर, दो वेल्डिंग होल्डर, 13 वायरिंग बोर्ड, कप सीटर के दो नग और एक रॉकेट सेट भी बरामद किया गया है।

वहीं मौके से बाइंडर, समानांतर कीट, ग्राइंडिंग बनाने वाला उपकरण, ड्रिल बिट, टेप रिंच, स्पैनर, वी-बेल्ट और बेंच वाइस सहित अन्य तकनीकी सामग्री भी मिली है।हालांकि प्रेस विज्ञप्ति में इन उपकरणों के उपयोग, इन्हें जंगल में छिपाकर रखने वाले लोगों और इनके किसी विशेष गतिविधि से जुड़े होने के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में शांति का वातावरण बनाए रखने और विकास गतिविधियों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।फिलहाल नारायणपुर पुलिस का कहना है कि नक्सल मुक्ति के बाद भी सुरक्षा बलों की सतर्कता में कोई कमी नहीं आई है। जिले के अंदरूनी और जंगल क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ सघन सर्च अभियान जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल कायम रखा जा सके।

छग कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत का जशपुर दौरे पर



जशपुरनगर। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी एवं झारखंड के लोहरदगा से सांसद सुखदेव राम भगत 16 नवंबर को एक दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचेंगे। उनके इस दौरे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि उनके स्वागत और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेस नेता भी जशपुर पहुंचेंगे।

जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष यूडी मिंज ने संगठन प्रभारी के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि सुखदेव भगत 16 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची से जशपुर पहुंचेंगे।छत्तीसगढ़ और झारखंड की अंतरराज्यीय सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री उमेश पटेल सहित छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। स्वागत कार्यक्रम के बाद सुखदेव भगत शंख से सीधे जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके बाद सौगड़ा आश्रम जाकर मां काली और गुरुपद संभवराम जी का आशीर्वाद लेंगे। अपने प्रवास के अंतिम चरण में सुखदेव भगत पत्थलगांव पहुंचेंगे।

यहां वे कांग्रेस के दिवंगत नेता हरगोविंद अग्रवाल के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे आगे के लिए रवाना होंगे।पत्रकार वार्ता में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हीरू राम निकुंज, पूर्व जनपद अध्यक्ष शशि भगत, सहस्त्रांशु पाठक, महेंद्र अग्रवाल, सुमित शर्मा सहित जिला कांग्रेस कमेटी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कांग्रेस का एक वोट बीजेपी में चला जाता है, ईवीए में हुई है सेटिंगः डॉ चरणदास महंत



एमसीबी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत ने चिरमिरी में आयोजित जन चौपाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पांच वोटों में से एक वोट बीजेपी में चला जाता है। उन्होंने श्रृङ्खरू में सेटिंग कराए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए।

डॉ। महंत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर हिन्दू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हिन्दू राष्ट्र के विरोध में नहीं है, लेकिन देश में सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए।

लोकतंत्र की मजबूती सभी वर्गों की समान भागीदारी से ही संभव है। मतदाता सूची में 13 करोड़ वोट काटे गए हैं। यह संख्या छोटी नहीं है और इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जनता को जागरूक होने की जरुरत है- डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत चिरमिरी के मंडल पौड़ी और नागपुर चौराहा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एआईसीसी ऑब्जर्वर एवं अभियान प्रभारी डॉ. देवाशीष पटनायक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जन चौपाल में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, एसआईआर प्रक्रिया, मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी समेत नामों के स्थान पर स्थानों के नाम दर्ज होने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के कारण लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने नामों की जांच करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। चिरमिरी में आयोजित इन जन चौपालों के जरिए कांग्रेस ने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी राजनीतिक मुहिम को आगे बढ़ाया।

उपभोक्ता आयोग ने ई रिक्शा कंपनी को दिया झटका



बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के ग्राम मोहरा निवासी तुलस टंडन ने ?58500 की नकद राशि और शेष रकम फाइनेंस के माध्यम से एक ई-रिक्शा खरीदी। खरीदी के महज तीन महीने बाद ही वाहन में खराबी आने लगी। शोरूम में बनवाने दिया लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई बल्कि ईरिक्शा को शोरूम में ही रख लिया गया।

तहसील सुहेला के ग्राम मोहरा, भाटापारा निवासी तुलस टंडन ने बलराम टांडी, प्रोपराइटर एवं संचालक गैलेक्सी मोटर्स, रायपुर से ई-रिक्शा कार्ट खरीदा था। वाहन की कीमत ?58,500 नकद और शेष राशि फाइनेंस के माध्यम से चुकाई गई थी। वाहन खरीदने के करीब तीन महीने बाद ही उसमें तकनीकी खराबियां आने लगीं। परिवादी ने इसकी शिकायत संबंधित विक्रेता से की। शिकायत पर वाहन को मरम्मत के लिए शोरूम में रख लिया गया। करीब एक महीने बाद गियरबॉक्स बदलकर वाहन वापस किया गया, लेकिन अन्य पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर बाकी खराबियों का समाधान नहीं किया गया। वाहन वापस मिलने के महज एक सप्ताह बाद ही उसमें फिर खराबी आ गई। इसके बाद वाहन को दोबारा मरम्मत के लिए शोरूम में जमा कराया गया, लेकिन इस बार उसे सुधारकर परिवादी को वापस नहीं किया गया। वाहन का उपयोग नहीं कर पाने और वारंटी अवधि में भी समस्या का समाधान नहीं मिलने से परेशान होकर तुलस टंडन ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलौदाबाजार की अध्यक्ष रंजना दत्ता और सदस्य हरजीत सिंह चांवला और शारदा सोनी की पीठ ने की। आयोग ने परिवाद में प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित कानूनी प्रावधानों का परीक्षण किया। आयोग ने पाया कि वाहन खरीदने के तीन महीने के भीतर उसका गियरबॉक्स बदलने की नौबत आ गई थी। इसके बावजूद अन्य खराबियों को दूर नहीं किया गया। नए वाहन में लगातार खराबियां आना, उसका पूरी तरह बंद हो जाना और वारंटी अवधि में भी वाहन को पूर्ण रूप से सुधारकर उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराना, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को प्रमाणित करता है। आयोग ने इन परिस्थितियों के आधार पर विरोधी पक्षकार को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार माना।

आयोग ने अपने आदेश में विरोधी पक्षकार को निर्देश दिया है कि परिवादी को संबंधित वाहन उसकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार सुधारकर उपलब्ध कराया जाए अथवा वाहन का वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाए। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक परेशानी के लिए ?25,000 की क्षतिपूर्ति और मुकदमे में हुए खर्च के लिए ?10,000 देने का आदेश दिया गया है। इस तरह वाहन के सुधार या वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त ?35,000 की राशि भी परिवादी को दी जानी है। यह आदेश उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें वारंटी अवधि में वाहन या अन्य उत्पादों में खराबी आने के बावजूद विक्रेता अथवा कंपनी से उचित समाधान नहीं मिल पाता। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ता आयोग संबंधित पक्षकार को क्षतिपूर्ति और अन्य राहत देने का आदेश दे सकता है।

विधायक रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप



एमसीबी। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी देने के लिए एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष चंपादेवी पावले सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से देश की 568 अनुसूचित जनजाति बहुल विधानसभा सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और महापुरुषों के बलिदान को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

लगभग 55 साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। जनजाति समाज के लिए अलग से मंत्रालय का गठन भाजपा ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा बीजेपी ने की। आदिवासी नायकों को इतिहास में हाशिए पर रखा। साल 2022 में जनजाति महिला राष्ट्रपति के खिलाफ प्रत्याशी उतारा और उनके खिलाफ अपशब्दों का उपयोग कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया। आदिवासी महापुरुषों की वीरगाथा को दबाया गया, लोग 1857 की क्रांति को पहली क्रांति मानते हैं लेकिन जनजाति समाज बिहार के भागलपुर का एक आदिवासी युवक तिलका मांझी 1771 से लेकर 1784 तक अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। ऐसे कई आदिवासी महापुरुष है। 2014 के बाद जनजातियों के लिए भाजपा सरकार ने काम करना शुरू किया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहली बार जनजाति मंत्रालय गठन कर आदिवासियों के लिए काम किया गया - सत्यनारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पार्टी की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, त्याग और देश की आजादी में उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। प्रेसवार्ता के जरिए भाजपा ने जनजातीय गौरव दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने का संदेश दिया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

किसानों की गिरदावरी और डीसीएस में गड़बड़ी पर पटवारी निलंबित

बलौदाबाजार। किसानों के राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही और रिकॉर्ड में त्रुटियों की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।सिमगा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 21 में पदस्थ पटवारी मिलन दास कोसले को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत और प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद की गई है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी मिलन दास कोसले के विरुद्ध ग्रामीणों ने शासकीय कार्य नहीं किए जाने की शिकायत की थी। वहीं ग्राम मोहभट्ठा के किसानों ने डीसीएस और गिरदावरी कार्य में त्रुटियों को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रखी थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने प्रारंभिक परीक्षण कराया। इसमें शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर कलेक्टर ने निलंबन का आदेश जारी किया। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

11 राज्यों में 3.37 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा

भानुप्रतापपुर। जिले में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भानुप्रतापपुर पुलिस ने ऐसे दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके बैंक खाते का इस्तेमाल देश के 11 राज्यों में लोगों से ठगी गई रकम को हासिल करने और आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। इस बैंक खाते से जुड़ी शिकायतों में कुल 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा के संबंधित खाते में 67 हजार 850 रुपये की रकम होल्ड थी। पुलिस के मुताबिक, यह खाता साइबर ठगी के नेटवर्क में लेयर-1 म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। यानी ठगी का शिकार हुए लोगों की रकम सबसे पहले इसी खाते में जमा होती थी। इसके बाद रकम को दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था या निकाल लिया जाता था। दरअसल, गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल और पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद भानुप्रतापपुर पुलिस साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों की जांच कर रही थी।

तीन मंत्री देख रहे जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां

रायगढ़। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। ऐसे में आयोजन में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसके लिए राज्य सरकार के तीन-तीन मंत्री संगठन पदाधिकारी के साथ जुटे हैं। आयोजन को अंतिम रूप देने के लिए धरमजयगढ़ स्थित आयोजन स्थल पर एक तरफ जहां मंत्री ओपी चौधरी, राम विचार नेताम, केदार कश्यप मौजूद हैं, तो दूसरी ओर भाजपा संगठन की ओर से प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। धरमजयगढ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आम जनता की जानकारी के लिए तमाम शासकीय विभाग अपनी-अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाएंगे।

घर में घुसकर लाखों के जेवरात और नगद ले उड़े दो बदमाश

जांजगीर-चांपा। जिले में दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से लाखों रुपये के जेवरात और नगदी लूटने के मामले में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ यूलैण्डन यार्क के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम को आरोपियों की पहचान कर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। घटना अमरैया पारा वार्ड नंबर 23 की है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे दो नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर अकेली महिला को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली थी। इसी दौरान छत पर आहट सुनकर वह बाहर निकली, तो गमछे से चेहरा ढके दो युवक दिखाई दिए। आरोप है कि दोनों बदमाश महिला को जबरदस्ती कमरे में ले गए और अलमारी की चाबी मांगी। महिला के पास चाबी नहीं मिलने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद अलमारी में रखे करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 8 हजार रुपये नगद लेकर अपने साइकिल से फरार हो गए।

ग्राम डिंडौरी में सीएम साय ने दी कॉलेज की सौगात

लोरमी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के गृहग्राम डिंडौरी पहुंचे। आजादी के बाद यह पहली मौका है, जब किसी मुख्यमंत्री ने इस गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा की सौगात दी। प्रवास के दौरान उन्होंने मुंगेली जिले में 465 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू अपने बचपन और शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन अपने गृहग्राम डिंडौरी से पैदल चलकर ग्राम कंतेली स्कूली पढ़ाई करने जाते थे। उसी कंतेली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने नवीन महाविद्यालय का शुभारंभ किया। तोखन साहू ने कहा कि कतेली में महाविद्यालय शुरू होना उनके लिए गौरव और भावनात्मक क्षण है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

गंगरेल मड़ई विशेषः मां अंगारमोती से संतान सुख की कामना



धमतरी। छत्तीसगढ़ में मड़ई की अपनी एक अलग पहचान है। मड़ई यानी मेला।।। लेकिन ये मड़ई आम मेला की तरह सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। ये संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम है। हर मड़ई में अलग-अलग मान्यता और गांवों के देवी-देवता शामिल होते हैं। ऐसी ही एक मड़ई है धमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगारमोती मंदिर की मड़ई।

गंगरेल बांध के किनारे वनों से घिरे मंदिर में विराजित मां अंगारमोती को क्षेत्र के 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार, माता का प्राचीन स्थान चंवर गांव के आसपास महानदी और सूखी नदी के बीच स्थित क्षेत्र में था। उस समय आसपास के गांवों के लोग माता की पूजा-अर्चना करते थे और हर शुभ कार्य से पहले उनका आशीर्वाद लेते थे। गंगरेल बांध के निर्माण के दौरान क्षेत्र के कई गांव डूब प्रभावित हुए और ग्रामीणों को अपने पुराने निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा। इसी दौरान मां अंगारमोती को भी उनके प्राचीन स्थान से गंगरेल के किनारे पुनर्स्थापित किया गया। इसके बाद से माता की पूजा-अर्चना और पारंपरिक मड़ई का आयोजन यहां निरंतर होता आ रहा है। आज भी 52 गांवों के देवी-देवताओं का माता के दरबार में पहुंचना पुराने गांवों, उनकी संस्कृति और सामूहिक आस्था से जुड़ी परंपरा का प्रतीक माना जाता है। मां अंगारमोती को लेकर क्षेत्र में एक विशेष मान्यता प्रचलित है कि माता कुंवारी थीं। इसी विश्वास के चलते मड़ई में संतान की कामना लेकर पहुंचने वाली महिलाएं खुले बालों में माता के दरबार आती हैं।

हाथों में नारियल, फूल और अगरबत्ती लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंदिर परिसर में धीरे-धीरे महिलाओं की लंबी कतार लग जाती है। हर महिला के मन में अपनी अलग मनोकामना और माता के प्रति गहरी श्रद्धा होती है। कोई वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रही होती है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद लेकर माता के सामने शीश नवाती है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक पूजा विधि में शामिल होकर माता से आशीर्वाद मांगती हैं।

मां अंगारमोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवराखन लाल मरई ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष महिलाओं के पंजीयन में काफी वृद्धि हुई है। पिछले साल करीब 800 महिलाओं ने पंजीयन कराया था, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 1600 हो गई है। उन्होंने कहा कि माता के प्रति लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ रही है और अब दूसरे राज्यों से भी महिलाएं यहां पहुंच रही हैं। मरई के अनुसार, मड़ई में 52 गांवों के देवी-देवताओं का शामिल होना इस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।

लिव इन पार्टनर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार



बलौदाबाजार। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रवान में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 59 वर्षीय घनसाय विश्वकर्मा पर अपनी लिव-इन पार्टनर रेवती जायसवाल की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, घटना से पहले दोनों ने शराब पी रखी थी। इसके बाद उनके बीच विवाद हुआ। इसी विवाद के दौरान आरोपी ने रेवती की हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा ने किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 12 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को ग्राम रवान में महिला की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला कि 11 नवंबर की रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में दोनों के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है। लड़ाई झगड़े के बाद आरोपी ने महिला को डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी।जांच में सामने आया कि दोनों पिछले करीब सात वर्षों से पति-पत्नी की तरह एक साथ रह रहे थे। परिवार में उनके साथ कोई अन्य सदस्य नहीं रहता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया।गवाहों के बयान लिए गए और शव पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार भेजा गया। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने, वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा और खून से सना गिलास जब्त किया है।

एनसीपी : भय और भ्रम के बीच अटका पुनर्मिलन

अमिताभ श्रीवास्तव

सुख हो या फिर दु:ख, राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के नेताओं के बीच मेल-मिलाप कुछ इस तरह होने लगता है, जैसे उनका विलय समीप आ चुका है। यहां तक कि अनेक बड़बोले नेता पुनर्मिलन की चर्चाओं को हवा देने में जुट जाते हैं। अंत में नतीजा वही होता है, जो सबको दिखता है। दोनों गुट अपनी राह पर अलग-अलग चलते दिखते हैं। कमोबेश यही स्थिति पिछले कुछ दिनों से दिख रही है। राकांपा प्रमुख अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और उनसे मिलने पहुंचने वाले नेता बाहर राजनीतिक चर्चाओं को गरमा रहे हैं। राकांपा के दोनों गुटों के एक साथ आने की खबरों की पुष्टि के लिए संपर्क करने पर पवार परिवार की ननद-भाभी स्पष्ट इंकार कर देती हैं। सुनेत्रा पवार विलय की बातचीत को मानती ही नहीं, जबकि सुप्रिया सुले के अनुसार एकीकरण का विषय अजित पवार की असामयिक मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। फिर भी राकांपा के एक होने का मुद्दा सामने है। जिसके बार-बार बाहर आने से यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि विलय आवश्यकता है या हवाबाजी के लिए तैयार एक मसाला है। कार्यकर्ताओं से अधिक नेताओं की पार्टी राकांपा में हर एक व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना लाजिमी है। दल के अजित पवार गुट में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे आदि जैसे नेतृत्वकर्ताओं को पार्टी की सामान्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर नेताओं की अलग-अलग अपनी धाक और साख है। शरद पवार गुट में सुप्रिया सुले के बाद जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे, रोहित पवार जैसे नेता हैं। इसका अपना क्षेत्रीय नेतृत्व और प्रभाव है। हालांकि इनके बीच पार्टी से सीधे जुड़े कार्यकर्ताओं की फौज अवसर मात्र तक सीमित है। चुनाव हो या फिर कोई आयोजन, क्षेत्र के नेताओं की अपनी ताकत रंग लाती है। उसका अपना साम्राज्य पार्टी को ताकत देता है। यह स्थिति अलग-अलग रहने से अनेक नेताओं को महत्व मिला हुआ है और साथ होने के बाद संख्या बढ़ने पर स्थितियां साझा करनी पड़ सकती हैं। अवश्य ही महत्व में कमी राजनीति में चिंता ही नहीं, भय का विषय भी है। जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। एकजुट राकांपा के सापेक्ष देखा जाए तो हर नेता को अपनी हैसियत का अंदाज लग जाता है। उधर, शिवसेना के दो गुटों की तरह संपूर्ण राकांपा की स्थिति नहीं है, जिसमें रिश्ते-नाते, तीज-त्यौहार, समारोह सब में साथ होने के बावजूद 'सेनाओं' के एकीकरण की चर्चा कभी संदर्भ में नहीं आती है। राकांपा में स्पष्ट रूप से दो गुट चुनावी स्पर्धा के बावजूद दोनों के नेता अक्सर अनेक अवसरों पर मिलते देखे जाते हैं। जिसमें उन्हें कोई समस्या नहीं होती है और एकीकरण की बात करने पर कोई एतराज नहीं होता है। यहां तक कि कई नेता खुलकर पुनर्मिलन की आवश्यकता बताते हैं। यदि पार्टी का पूर्व इतिहास देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार बगावत और दो बार अपनी पार्टी का गठन किया। जिसमें से एक बार अपने दल का कांग्रेस में विलय किया। तीसरी बार बनाई राकांपा के किसी विलय से पहले उसका विघटन हुआ। इसीलिए अब एकीकरण की बात उठी है। यही कारण है कि राकांपा के लिए टूटना और जुड़ना कोई नई सोच नहीं है। इस बार समस्या पार्टी नेतृत्व से अधिक नेताओं की है, जिनका अपना दायरा है। जिसे वह बनाए रखना चाहते हैं। इसी कारण अक्सर उनकी नीयत पर भी सवाल उठते हैं।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में पीडीए का सियासी इम्तिहान

सत्येंद्र प्रताप सिंह

2024 और 2026 दोनों वर्षों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में ऐसे चुनावी झटके लगे हैं, जिन्हें 2027 की तैयारी के संदर्भ में एक साथ देखना जरूरी है कि दोनों वर्षों के परिणाम क्या संकेत देते हैं? हालांकि दोनों चुनावों की प्रकृति अलग है। भाजपा के सामाजिक समीकरण और राजनीति को पहला झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का स्थान हासिल किया। कांग्रेस को छह सीटें मिलीं, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुला। वोट प्रतिशत की तस्वीर भी महत्वपूर्ण थी।

भाजपा को 41.36 प्रतिशत वोट मिले, जबकि सपा का वोट शेयर 33.60 प्रतिशत रहा। 2019 के मुकाबले भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट आई और सपा ने अपना समर्थन बढ़ाया। बसपा का वोट शेयर भी घटकर 9.39 प्रतिशत रह गया। इस परिणाम ने दिखाया कि भाजपा का मजबूत सामाजिक गठबंधन चुनौती से परे नहीं है। सपा ने यादव-मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर दूसरे पिछड़े और दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बनाई। पीडीए का राजनीतिक संदेश इसी पृष्ठभूमि में प्रभावी हुआ। हालांकि भाजपा का वोट प्रतिशत सपा से अधिक रहा। इसलिए 2024 को भाजपा के सामाजिक आधार के पूरी तरह टूटने के रूप में देखना सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर स्पष्ट हुआ कि विपक्षी एकजुटता और सामाजिक समीकरणों में बदलाव भाजपा की सीटों को प्रभावित कर सकते हैं।

2026 के विधान परिषद चुनाव ने इस बहस को नया संदर्भ दिया। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों में भाजपा ने छह और सपा ने पांच सीटें जीतीं। पिछले चुनाव के मुकाबले सपा ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई और निर्दलीय उम्मीदवारों की जगह इस बार मुकाबला मुख्यत: भाजपा और सपा के बीच सिमट गया।

कुल परिणाम भाजपा के पक्ष में छह-पांच का रहा, लेकिन सपा की पांच सीटों की जीत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर तब, जब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दोनों दलों के बीच यह सीधा मुकाबला हुआ है। इन परिणामों ने यह सवाल जरूर उठाया है कि क्या 2024 में विपक्ष के पक्ष में दिखाई दिया राजनीतिक बदलाव 2026 में भी कुछ निर्वाचन



क्षेत्रों में कायम है? विधान परिषद चुनाव का सबसे चर्चित परिणाम वाराणसी से आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा ने शिक्षक और स्नातक, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की। स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा को 55,046 और भाजपा के केदारनाथ सिंह को 35,114 वोट मिले। जीत का अंतर 19,932 मत रहा। शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव ने 11,612 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र को 6,597 वोट मिले। यहां जीत का अंतर 5,015 मत था।

वाराणसी में दोनों सीटों पर सपा की जीत को केवल स्थानीय परिणाम मानकर छोड़ना आसान नहीं है। यह भाजपा के लिए राजनीतिक और प्रतीकात्मक, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां हार ने स्थानीय संगठन, उम्मीदवारों के चयन और शिक्षक-स्नातक मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े किए हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में रोजगार, भर्ती, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की समस्याएं जैसे मुद्दे प्रभाव डालते हैं। इसलिए इस परिणाम को शिक्षित वर्ग के एक हिस्से में असंतोष के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है।

लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता आम विधानसभा मतदाताओं से अलग हैं। वाराणसी की जीत को पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जनमत का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। फिर भी 2027 से पहले सपा के लिए यह राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक उत्साह का विषय जरूर है।

दोनों चुनावों की प्रकृति अलग है। लोकसभा चुनाव में व्यापक मतदाता हिस्सा लेता है, जबकि विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक चुनाव सीमित मतदाता वर्ग के बीच होते हैं। इसलिए दोनों के परिणामों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती।फिर भी एक साझा सवाल उभरता है- क्या भाजपा के खिलाफ अलग-अलग सामाजिक और पेशागत समूहों में असंतोष विपक्ष को अवसर दे रहा है?

2024 में सपा ने सामाजिक गठबंधन के सहारे लोकसभा में बड़ी सफलता हासिल की। 2026 में विधान परिषद की पांच सीटों पर जीत ने दिखाया कि पार्टी कुछ विशिष्ट मतदाता वर्गों में भी अपनी पकड़ बना रही है।

भाजपा के लिए चुनौती इन संकेतों को समझने और अपने संगठन तथा सामाजिक गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की है। विपक्ष के लिए चुनौती इन अलग-अलग सफलताओं को एक व्यापक राजनीतिक विकल्प में बदलने की है। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यादवों और मुस्लिम मतदाताओं से आगे गैर-यादव पिछड़ों तथा गैर-जाटव दलितों का भरोसा भी सपा के साथ बना रहता है। कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, राजभर और कश्यप जैसे समुदायों का अपना राजनीतिक प्रभाव है। इनमें से कई भाजपा के सामाजिक गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। 2024 में कुछ वर्गों के मतदान व्यवहार में बदलाव के संकेत मिले, लेकिन इसे स्थायी बदलाव मानना जल्दबाजी होगी।

दलित राजनीति में बसपा की कमजोरी ने सपा के सामने अवसर जरूर खोला है। लेकिन जाटव मतदाताओं के बीच मायावती की पहचान और गैर-जाटव दलितों की अलग राजनीतिक आकांक्षाओं को समझना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद भी दलित राजनीति में अपनी स्वतंत्र जगह बना रहे हैं। 2027 में उनका सपा के साथ आना या अलग चुनाव लड़ना विपक्ष के सामाजिक गणित को प्रभावित कर सकता है।

अखिलेश यादव को केवल जातीय नारों से आगे बढ़कर संगठन, टिकट वितरण और राजनीतिक नेतृत्व में इन समुदायों को वास्तविक हिस्सेदारी देनी होगी। पीडीए तभी टिकाऊ गठबंधन बनेगा, जब हर वर्ग को उसमें अपना प्रतिनिधित्व दिखाई देगा।

मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा 2024 में भाजपा के विरोध में विपक्षी गठबंधन के साथ गया। 2027 में सपा के लिए इस समर्थन को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल भी उतने ही अहम हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की सक्रियता सपा के सामने एक अतिरिक्त चुनौती खड़ी कर सकती है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सीटों और नेतृत्व पर सहमति बनाना भी आसान नहीं होगा।

2024 में सपा-कांग्रेस तालमेल सफल रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय दावेदारों और सीटों का बंटवारा अधिक जटिल हो सकता है। यदि विपक्षी दल आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझे, तो 2024 में बना चुनावी तालमेल कमजोर पड़ सकता है। दूसरी ओर भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे सहयोगी दल हैं। इनके जरिए भाजपा विभिन्न सामाजिक समूहों तक अपनी पहुंच बनाए रखने की कोशिश करेगी।

भाजपा की ताकत केवल सवर्ण मतदाताओं के समर्थन पर नहीं टिकी है। गैर-यादव पिछड़े, गैर-जाटव दलित और विभिन्न सामाजिक समुदाय उसके व्यापक राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा हैं। इसके साथ हिंदुत्व, संगठनात्मक नेटवर्क, सरकारी योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व भी उसकी ताकत का आधार हैं। 2024 में भाजपा के वोट प्रतिशत और सीटों में गिरावट ने इस गठबंधन की सीमाएं उजागर कीं। 2026 के विधान परिषद चुनाव में सपा की पांच सीटों और वाराणसी की दोनों जीत ने विपक्ष को एक नया राजनीतिक संदर्भ दिया। लेकिन भाजपा ने 11 में से छह सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी भी कायम रखी। इसलिए सवाल भाजपा के सामाजिक आधार के खत्म होने का नहीं, बल्कि उसमें संभावित बदलाव का है। क्या गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच 2024 में दिखा बदलाव आगे भी जारी रहेगा? क्या वाराणसी जैसे परिणाम दूसरे क्षेत्रों में भी दोहराए जा सकते हैं? इन सवालों का जवाब विधानसभा चुनाव के व्यापक मतदाता वर्ग में ही मिलेगा।

2024 और 2026 के चुनावी परिणामों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और सपा के बीच मुकाबले को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव केवल पिछले चुनावों के परिणामों की पुनरावृत्ति नहीं होगा। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेंगे। अखिलेश यादव को इन मुद्दों पर स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व का भरोसा भी देना होगा। भाजपा के सामने अपने मौजूदा सामाजिक गठबंधन को बनाए रखने और स्थानीय असंतोष का जवाब देने की चुनौती होगी। सपा के सामने 2024 के समर्थन को स्थायी बनाने, छोटे दलों और कांग्रेस के साथ तालमेल रखने तथा पीडीए के भीतर सभी वर्गों को उचित राजनीतिक जगह देने की परीक्षा होगी।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

23-योगाचार का विज्ञानवाद



गतांक से आगे...

विज्ञानवादी ने याह्य पदार्थों के खण्डन में अनेक युक्तियाँ दी हैं जिनमें परमाणुबाद और अवयविवाद का खण्डन करके यह सिद्ध किया है कि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व सम्भव ही नहीं। उन युक्तियों का निरूपण. इस संक्षिप्त निबन्ध में सम्भव नहीं है।

आलय विज्ञान : विज्ञानवाद का, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, आधार तर्क यह है कि स्वसंवेदन अर्थात् हमें ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता, अर्थात् ज्ञान का अस्तित्व और उसका प्रत्यक्ष हमारा आधारभूत सत्य है। परन्तु फिर भी वह स्वसंवेद्य-मान क्षणिक ज्ञानों को परमार्थ सत् नहीं मानता।

विज्ञानवादी के अनुसार सत्य के तीन स्तर हैं:- एक परिनिष्पन्न लक्षण अर्थात् परमार्थ सत्य, दूसरा परतन्त्र लक्षण अर्थात् व्यावहारिक सत्य और तीसरा परिकल्पित लक्षण अर्थात् कल्पनात्मक सत्य। परमार्थ सत्य क्या है? प्रत्येक क्षण अनुभव में आने वाले अनन्त विज्ञानों को प्रवृत्तिविज्ञान कहा गया है। इन प्रवृत्तिविज्ञानों से परे एक आलयविज्ञान है जो निरपेक्ष (Absolute) तत्त्व है जिसमें एक प्रकार से सारे प्रवृत्ति विज्ञान समा जाते हैं। जिस प्रकार माध्यमिक शून्यवाद में निरपेक्ष का स्वरूप शून्य है उसी प्रकार योगाचार का निरपेक्ष तत्त्व आलयविज्ञान के रूप में है।

आलय-विज्ञान ही निर्वाण या बोधि का स्वरूप है। यह आलयविज्ञान ही परिनिष्पन्न लक्षण सत्य है अर्थात् परमार्थ सत्य है।

इस आलयविज्ञान का शुद्ध स्वरूप योग के द्वारा प्राप्त होता है जिस के कारण ही इस सम्प्रदाय का नाम योगाचार है। बाकी प्रवृत्ति-विज्ञान या प्रवृत्तिविज्ञानों से प्रकट होने वाला जगत् परमार्थ सत्य नहीं है प्रत्युत परतन्त्रलक्षण सत्य है।

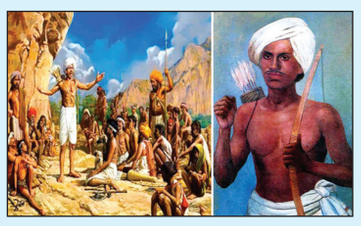
क्रमश: ...

भगवान बिरसा मुंडा

प्रो. संजय द्विवेदी

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को रांची जिले के उलिहतु गाँव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलिहतु से कुरुमब्दा आकर बस गया। जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे।

भारतीय समाज की स्मृति बहुत अल्प है। अपने नायकों और उनके कामों को भूल जाना यहां बहुत आसान है। ऐसे ही नायक हैं-भगवान बिरसा मुंडा। जिन्हें हमने लगभग भुला सा दिया था। कुछ अरसे पहले झारखंड के इस अप्रतिम नायक की राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई स्मृति बनती हो। किंतु नए समय में जब भारत अपने



सांस्कृतिक नायकों को खोजकर उनके बारे में पढ़ रहा है, तब उसमें बिरसा की याद बहुत स्वाभाविक और मार्मिक हो उठती है। इसी बीच भारत सरकार ने वर्ष 2021 में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। जाहिर है इसका उद्देश्य हमारे जनजातीय नायकों और जनजातीय समाज की समृद्ध कला, संस्कृति, बोलियों और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करना तथा उनके त्याग-बलिदान को समाज के सामने लाना रहा।

अंग्रेजी राज में जनजातीय समाज की दुर्दशा, उनके दमन और स्थानीय साहूकारों द्वारा अपने समाज का शोषण देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। अंग्रेजी राज की दमनकारी नीतियां उनके निशाने पर थीं। जनजातीय समाज की स्वायत्तता बची और बनी रहे इसी भाव से उनके मन में क्रांतिकारी विचार आए। इससे ही उलगुलान (महाविद्रोह) की भावभूमि बनी। 1899-1900 के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में महान सशस्त्र विद्रोह हुआ, इसे ही इतिहास में उलगुलान के नाम से जाना गया। यह सिर्फ राजनीतिक विद्रोह नहीं था वरन जल,जंगल, जमीन पर जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए शंखनाद भी था। इस आंदोलन ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, एकता और सांस्कृतिक स्वायत्तता का भी आधार तैयार किया। अपने इन्हीं सार्थक प्रयासों के नाते भगवान बिरसा को धरती आबा (यानी धरती पिता) कहा गया। लोकमन में उनकी स्मृति इतनी सघन है कि वे तमाम युवाओं के आदर्श बन गए। संघर्ष के प्रतीक और अप्रतिम नायक तो बने ही। उलगुलान, निस्संदेह, एक विद्रोह से कहीं बढ़कर था। यह लड़ाई न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए थी। भगवान बिरसा मुंडा की सूझबूझ ने एक ओर जनजातीय लोगों द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी ज़मीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार को, तो दूसरी तरफ जनजातीय रीति-रिवाज़ों और सामाजिक मूल्यों के महत्व को एक साथ जोड़ दिया। महात्मा गांधी की तरह, उनका संघर्ष भी न्याय और सत्य की खोज से प्रेरित था।

घुसपैठ : बांग्लादेश के लिए सिरदर्द बने रोहिंग्या घुसपैठिये

नीरज कुमार दुबे

खुद घुसपैठ की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला बांग्लादेश आज रोहिंग्या घुसपैठियों की एक ऐसी बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, जिसने उसकी आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। म्यांमार से लगी सीमा पर हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ म्यांमार के रखाइन प्रांत में सशस्त्र संगठन अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिंसा और विस्थापन से परेशान रोहिंग्या परिवार बांग्लादेश में दाखिल होने के रास्ते तलाश रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश को म्यांमार की केंद्रीय सत्ता के बजाय अराकान आर्मी से भी बातचीत करनी पड़ रही है।

यहां सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है? क्या उसकी सीमा अब केवल शरणार्थियों की आवाजाही का रास्ता बनकर रह गई है? और क्या रोहिंग्या संकट आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए एक बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप लेने जा रहा है?

हम आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार संबंधी विशेष रैपोर्टियर केली ई. करी से मुलाकात के दौरान एक बेहद गंभीर आंकड़ा सामने रखा। उनके मुताबिक बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में संख्या इससे कम दर्ज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा बड़ी बताई जा रही है।

इनमें से अधिकांश रोहिंग्या कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अगस्त 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद अपना घर छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने साफ कहा कि इतने बड़े शरणार्थी समुदाय को लंबे समय तक अपने यहां रखने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। ढाका ने अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर समन्वित कूटनीतिक दबाव



बनाने की मांग की है।

ढाका में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश आखिर कब तक इस आबादी का बोझ उठाएगा? जब शरणार्थियों की वापसी का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा और सीमा पार हिंसा लगातार जारी है, तब ढाका के सामने संकट और गहराता जा रहा है।

साथ ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में अब वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है। अराकान आर्मी ने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया है और बांग्लादेश से लगी सीमा के बड़े हिस्से पर भी उसका प्रभाव है। यानी बांग्लादेश के सामने अब एक ऐसी ताकत खड़ी है, जो म्यांमार की आधिकारिक सरकार नहीं है, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण उसी का है।

यही वजह है कि बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 8 नवंबर को खुलासा किया कि ढाका म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ-साथ अराकान आर्मी से भी बातचीत कर रहा है। रोहिंग्याओं की वापसी के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने वाली समिति गठित की गई है और इस समिति के तहत दोनों पक्षों से संपर्क साधा जा रहा है। देखा जाये तो यह घटनाक्रम अपने आप में बांग्लादेश की कूटनीतिक मजबूरी को उजागर करता है। जिस संगठन के नियंत्रण वाले इलाके से रोहिंग्याओं का पलायन हो रहा है, उसी संगठन से अब बांग्लादेश को बातचीत करनी पड़ रही है। यह संकेत है कि म्यांमार की सीमा पर सत्ता और नियंत्रण का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है।

साथ ही सीमा पर बिगड़ते हालात का ताजा उदाहरण 38 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी है। बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने टेकनाफ इलाके में म्यांमार से मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए पहुंचे 38 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। इनमें आठ पुरुष, 14 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को नाव के जरिए बांग्लादेश लाने के लिए मोटी रकम वसूली गई थी। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक स्थानीय महिला के घर में ठहराया गया था। सूचना मिलने पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने छापा मारकर सभी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की है।

यह घटना बताती है कि म्यांमार में जारी हिंसा अब बांग्लादेश की सीमा पर किस तरह दबाव बना रही है। घुसपैठ के लिए केवल जमीन का रास्ता ही नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग भी इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय नाव मालिकों और बिचौलियों की भूमिका इस समस्या को और गंभीर बनाती है।

देखा जाये तो रोहिंग्या संकट अब केवल शरणार्थियों को भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह गया है। कॉक्स बाजार में बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मौजूदगी ने स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही अवैध आवाजाही, मानव तस्करी और संगठित घुसपैठ के नेटवर्क की आशंकाएं भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं। साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा, जबरन विस्थापन और आवाजाही पर पाबंदियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटिश सरकार की जनवरी 2026 की देश संबंधी रिपोर्ट में भी अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों और आवाजाही पर प्रतिबंधों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान हिंसा के कारण दो लाख तक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे।

ऐसे में बांग्लादेश के लिए मुश्किल दोहरी है। एक तरफ पहले से मौजूद 15 लाख से अधिक लोगों का बोझ है, दूसरी तरफ म्यांमार में जारी संघर्ष नए लोगों को सीमा पार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो शरणार्थी शिविरों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर दबाव और बढ़ सकता है।

उधर, बांग्लादेश अब इस संकट से निकलने के लिए भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रभावशाली पक्षों से म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर केली करी के साथ बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्याओं को उनके देश में नागरिकता और बुनियादी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े मामले में अपेक्षित फैसले को भी बांग्लादेश अहम मान रहा है। हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फैसले से अपने आप रोहिंग्याओं की वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी। इसके लिए म्यांमार के भीतर वास्तविक राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव जरूरी होगा।

बहरहाल, देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी म्यांमार सीमा पर बदलते सत्ता समीकरणों के बीच प्रभावी नियंत्रण बनाए रख पाएगा? जब सीमा के दूसरी तरफ अराकान आर्मी का दबदबा है, म्यांमार की केंद्रीय सत्ता कमजोर है और समुद्री रास्तों से रोहिंग्याओं की आवाजाही जारी है, तब ढाका के सामने चुनौती केवल घुसपैठ रोकने की नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता बचाने की भी है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या संकट अब एक ऐसा सुरक्षा और कूटनीतिक जाल बनता जा रहा है, जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।

आज का इतिहास

1830 समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए।
1875 बिरसा मुण्डा, भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक आदिवासी नेता का जन्म हुआ।
1920 जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई।
1923 जर्मनी में मुद्रा स्फीर्ती की दर अत्यधिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंची।
1936 नाजी जर्मनी और जापान के बीच कोमिंट्रन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किये गये।
1947 विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया।
1949 महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोड से और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फाँसी दी गई।
1955 पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
1961 संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई।
1988 पी.एल.ओ. के अध्यक्ष यासर अराफात द्वारा फ़िलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित।
1989 पाकिस्तान के कराची में वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।
1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपना एशियाई देशों भारत एवं पाकिस्तान का दौरा रद्द किया।
2000 फिजी में तख्ता पलट अवैध घोषित।
2000 झारखंड भारत का 28वां राज्य बना।
2001 अलकायदा के ठिकाने से परमाणु बम बनाने सम्बन्धी दस्तावेज मिले।
2003 तुर्की के इस्ताम्बल शहर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास हुए बम विस्फोट में 16 लोगों की मृत्यु और 150 घायल।
2004 आस्ट्रेलिया के नामकरण की दो सौवीं वर्षगांठ मनी। अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
2007 चिली में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकम्प आया। एरियाना-5 रॉकेट ने ब्रिटेन व ब्राजील के दूरसंचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया।
2008 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर वाई वेणुगोपाल रेड्डी को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जाँच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया गया। योगेन्द्र मकबाल ने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई।
2008 योगेन्द्र मकबाल ने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई।
2012 शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने।

छठ पूजा और सियासत: आस्था के विस्तार के साथ पूर्वांचली वोटों का बदलता गणित

विनोद पाठक

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा के रूप में पहचानी जाने वाली छठ पूजा आज दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे महानगरों के सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कभी प्रवासी परिवारों के बीच सीमित संसाधनों और निजी आस्था के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व अब विशाल घाटों, सरकारी व्यवस्थाओं, सार्वजनिक आयोजनों और राजनीतिक बधाई संदेशों के बीच अपनी व्यापक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस बदलाव के पीछे जहां प्रवास के साथ सांस्कृतिक पहचान का विस्तार है, वहीं महानगरों में पूर्वांचली मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक अहमियत भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि, छठ की लोकप्रियता और उसके इर्द-गिर्द विकसित हुई राजनीति को समझने के लिए इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग देखना आवश्यक है। दरअसल, दो-ढाई दशक पहले तक दिल्ली में छठ पूजा का स्वरूप आज जैसा नहीं था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए परिवार अपने घरों, आसपास के तालाबों अथवा यमुना के किनारे छोटे-छोटे समूहों में यह पर्व मनाते थे। परिवार के सदस्य जुटते, परिचितों और रिश्तेदारों के बीच प्रसाद बांटा जाता और अगले दिन सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाते। न शहर भर में बड़े-बड़े स्वागत द्वार दिखाई देते थे, न राजनीतिक दलों के नेताओं के चेहरे वाले बधाई पोस्टर और न ही छठ घाटों पर जनप्रतिनिधियों की वैसी मौजूदगी होती थी, जैसी आज देखने को मिलती है। मुंबई में भी स्थिति बहुत अलग नहीं थी। वहां छठ मनाने वाले परिवारों ने समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों पर छोटे सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से इस परंपरा को जीवित रखा। उस समय यह मुख्यत: प्रवासी समाज का अपना आयोजन था, लेकिन धीरे-धीरे यह महानगरों के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गया। इस बदलाव को केवल धार्मिक आस्था के विस्तार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे दशकों से जारी वह सामाजिक परिवर्तन है, जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार, शिक्षा व बेहतर अवसरों की तलाश में दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम तथा देश के दूसरे शहरों में पहुंचे। उन्होंने महानगरों की अर्थव्यवस्था में अपना श्रम और योगदान दिया, परिवार बसाए और धीरे-धीरे स्थानीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन गए। अपने साथ वे भाषा, खानपान, लोकगीत, रीति-रिवाज और त्योहार भी लेकर आए। जैसे-जैसे प्रवासी आबादी का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे अपनी सांस्कृतिक पहचान को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने और उसे सामाजिक मान्यता दिलाने की आकांक्षा भी मजबूत होती गई। छठ पूजा इस पहचान की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरी। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल एक दिन का धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि चार दिनों तक चलने वाली सामूहिक साधना है। नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक चलने वाली इस परंपरा में परिवार, समाज, प्रकृति और आस्था का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इसमें डूबते सूर्य के साथ उगते सूर्य की भी उपासना होती है। महानगरों की भागदौड़ और व्यस्त जीवन के बीच रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए छठ अपनी मिट्टी, परंपरा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का भावनात्मक माध्यम बन गया। यही कारण है कि आज महानगरों में जन्मी नई पीढ़ी भी इस पर्व को उतनी ही आत्मीयता से अपनाती है। इस कहानी का दूसरा पहलू राजनीति है। जिस समय महानगरों में पूर्वांचली आबादी का विस्तार हो रहा था, उसी समय उसकी चुनावी प्रासंगिकता भी बढ़ने लगी।

लोकतंत्र में किसी समुदाय की सामाजिक उपस्थिति



जब चुनावी महत्व हासिल करती है तो राजनीतिक दलों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर जाता है। दिल्ली इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यहां पूर्वांचली मतदाताओं की अहमियत दो दशक पहले ही पहचानी जाने लगी थी।

वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के आसपास छठ पूजा और पूर्वांचली समाज राजनीतिक चर्चा के महत्वपूर्ण विषय बनने लगे थे। राजनीतिक दलों को समझ आने लगा था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों को केवल बाहरी अथवा अस्थायी आबादी मानना बदलती शहरी राजनीति की वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा होगा। वे शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले नागरिक होने के साथ-साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मतदाता भी बन चुके थे।

इसके बाद छठ पूजा के आयोजनों में राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ती गई। भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस समुदाय से संवाद स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए। नेताओं ने छठ घाटों पर पहुंचना शुरू किया, आयोजन समितियों को सहयोग दिया और सार्वजनिक सुविधाओं की मांग को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। दिल्ली में छठ पर सार्वजनिक अवकाश की मांग भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनी।

वर्ष 2014 में इस पर्व को सार्वजनिक अवकाश की मान्यता मिलने और 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा इसे राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने से इसकी संस्थागत स्वीकार्यता और मजबूत हुई। यह केवल एक धार्मिक पर्व को सरकारी मान्यता मिलने का मामला नहीं था, बल्कि महानगर की सामाजिक संरचना में पूर्वांचली समाज की बढ़ती उपस्थिति का भी संकेत था।

यहां राजनीति के बदलते स्वरूप को समझना जरूरी है। पहले राजनीतिक दल किसी समुदाय से मुख्यत: उसकी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के आधार पर संवाद करते थे, लेकिन अब उसकी सांस्कृतिक पहचान भी राजनीतिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है।

छठ घाटों पर नेताओं की मौजूदगी, सार्वजनिक बधाई संदेश, आयोजन समितियों से संपर्क और सरकारी सुविधाओं की घोषणाएं इसी बदली हुई राजनीतिक कार्यशैली के उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों के बीच यह प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देने लगी है कि किसने अधिक घाट बनवाए, किसने बेहतर व्यवस्था की और किसने श्रद्धालुओं के लिए परिवहन, सफाई, पेयजल तथा रोशनी की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। चुनाव नजदीक आते ही इन आयोजनों की दृश्यता और बढ़ जाती है। बधाई पोस्टरों पर नेताओं की तस्वीरें और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति आस्था के साथ राजनीतिक संदेश भी जोड़ देती है।

मुंबई में छठ की कहानी भी इसी सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी है, हालांकि वहां इसका राजनीतिक संदर्भ कुछ अलग रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता और उत्तर भारतीयों की मौजूदगी को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं। ऐसे वातावरण में छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि प्रवासी समाज की सांस्कृतिक उपस्थिति, सामुदायिक एकजुटता और अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता का प्रतीक भी बनी।

विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए छठ आयोजनों में भागीदारी की। कभी सीमित संसाधनों के बीच समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजन आज मुंबई के अनेक हिस्सों में बड़े सामुदायिक उत्सव का रूप ले चुके हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या पूर्वांचली समाज को एक संगठित वोट बैंक के रूप में देखा जा सकता है? राजनीतिक दलों की रणनीति में ऐसी प्रवृत्ति अवश्य दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक और जटिल है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों की जातीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है।

उनकी प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं भी अलग-अलग हैं। किसी के लिए रोजगार और महंगाई महत्वपूर्ण है, तो किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा। केवल क्षेत्रीय पहचान के आधार पर उनके मतदान व्यवहार को समझना उनकी राजनीतिक चेतना और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को कम करके आंकना होगा।

छठ के घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन का प्रमाण मानना भी उचित नहीं है। वहां उपस्थित लोगों की आस्था साझा हो सकती है, लेकिन उनकी राजनीतिक पसंद अलग-अलग हो सकती है। किसी नेता का घाट पर पहुंचना उसे स्वत: उस समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बना देता।

इसी तरह किसी राजनीतिक दल द्वारा छठ के अवसर पर बेहतर व्यवस्था करना उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी और नागरिकों की सुविधा से जुड़ा विषय भी हो सकता है। हर सार्वजनिक पहल को चुनावी चश्मे से देखना भी उतना ही अनुचित होगा, जितना राजनीति में सांस्कृतिक आयोजनों के महत्व को पूरी तरह नकार देना।

राजशाही का विस्तार या लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान?

पूरन चंद सरीन

नवम्बर 14 को नेहरू और 19 को इंदिरा गांधी का जन्म और अब 10 तारीख का दिन कांग्रेस परिवार की एक सदस्य सोनिया गांधी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन उनकी लिखी आत्मकथा का विमोचन हुआ और वह प्रायोजित तरीके से चर्चा का विषय बनी। कांग्रेसी हमेशा इस आत्ममुग्धता या गलतफहमी में रहे हैं कि इस देश का शासन गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई अन्य दल या नेता चला ही नहीं सकता। असल में यह मानसिकता राजा-महाराजाओं के दौर की याद दिलाती है कि नाकाबिल होने पर भी शासन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा सकती। नेहरू-इंदिरा शासन और सोनिया गांधी, इन तीनों के दौर में भारत बदला, राजनीति बदली और सत्ता का स्वरूप भी। एक बात साफ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुखता से अपना योगदान देने और तुरंत उसका फल पा लेने का मतलब यह नहीं कि उस परिवार को देश की राजनीति पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी अधिकार मिलता जाए। सरदार पटेल का उदाहरण देकर यह बात सिद्ध की जा सकती है कि यदि उनकी नीति सफल नहीं होती तो आज देश न जाने कितने टुकड़ों में बंटा होता। आत्मकथा में रिश्तों, राजनीतिक घटनाओं और सत्ता के गलियारों के अनुभव इतिहास नहीं हैं। बर्नार्ड शा ने लिखा था कि आत्मकथाएं समय और सच का आईना नहीं होतीं। नेहरू ने स्वतंत्र भारत को आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा। संसदीय व्यवस्था, वैज्ञानिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को दिशा दी। विश्व राजनीति में भारत की पहचान बनाने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नेहरू का दूसरा पक्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल करने की ललक देश की घरेलू प्रशासनिक समस्याओं पर भारी पड़ी। अंग्रेजों की देन लाइसेंस-परमिट व्यवस्था और भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी कम होने की बजाय बढने लगी। यह स्थिति केवल नेहरू के कारण नहीं बनी थी, और भी तत्व इसमें शामिल थे लेकिन संरक्षण और आरक्षण को मजबूत आधार मिल गया। देशवासियों को इसका सामना अब तक करना पड़ रहा है और बिना रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में आज भी काम नहीं होता। उनकी राजनीतिक भूल 1959 में केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय था लेकिन यह सब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया कि यह अच्छा उदाहरण नहीं था। प्रश्न यह है कि क्या केंद्र की राजनीतिक असहमति किसी चुनी हुई राज्य सरकार को हटाने का पर्याप्त कारण हो सकती है। दुर्भाग्य से इंदिरा सरकार ने इसके कई उदाहरण पेश किए और वर्तमान सरकार भी इस परिपाटी पर चलने में पीछे नहीं है। विदेश नीति में चीन के साथ मित्रता को आंकने में हुई चूक ने 1962 की पराजय दी और देश को गहरा आघात पहुंचा। कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र और जनमत-संग्रह से जुड़ी उनकी नीतियों तथा बाद के फैसलों ने ऐसा गतिरोध पैदा किया कि आज भी भुगतना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता से अलग राजनीतिक शैली अपनाई। उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति और 1971 के युद्ध में विजय उनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष सत्ता का असाधारण केंद्रीकरण था। कांग्रेस संगठन धीरे-धीरे कमजोर हुआ।

पुन: राजनीति का केंद्र बिंदु बनती अयोध्या

मृत्युंजय दीक्षित

उच्चतम न्यायलय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य-भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है।अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज़ बुक में स्थान बना चुका है।अयोध्या विश्व के पर्यटन मानचित्र पर चमक रही है।अयोध्या की आर्थिकी में नए स्तर पर पहुँच चुकी है। चिर पुरातन अयोध्या पौराणिक मान्यताओं और आधुनिक विकास के समन्वय का प्रतीक बन गई है। इतने वर्षों में अयोध्या और अयोध्या से जुड़ा बहुत कुछ बदल गया है जो नहीं बदला है वो है अयोध्या को लेकर राजनीति का तापमान।

वैसे तो राम मंदिर और अयोध्या को लेकर भाजपा तथा उसके विरोधी दलों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं किन्तु अब कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात कहकर अयोध्या के नाम पर सियासत को नया रंग देने का दांव चला है। अखिलेश लम्बे समय से फैजाबाद की लोकसभा सीट पर सपा की जीत को ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं। सपा मुखिया अयोध्या को लेकर ऐसे चुनावी वादे कर रहे हैं कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए, वो अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, जो योगी जी पहले ही बना चुके हैं। सरकार बनने पर राम मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित जमीन घोटाले की जांच कराने की घोषणा कर रहे हैं, जो पहले से ही चल रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा



मुखिया पर हमलावर होना स्वाभाविक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर ही सपा मुखिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह पहले पूर्व में किए गए पापों के लिए माफी मांगे और फिर अयोध्या आयें।

अयोध्या के संत समाज ने भी सपा मुखिया से माफी मांगने की अपील करते हुए कहा है कि माफी मांगे बिना अखिलेश को अयोध्या की पंचकोसी की शास्त्रीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कारसेवकों के बलिदान की अनदेखी नहीं का जी सकती। संतों ने रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलवाने और संतो पर लाठीचार्ज कराने की घटनाओं पर सपा नेतृत्व से जवाब मांगा है। संतों का कहना है कि उन्हें अखिलेश के अयोध्या आने, रामलला के दर्शन करने या सरयू में स्नान करने पर आपत्ति नहीं है लेकिन कारसेवकों के बलिदान को अनदेखी कर उनका स्वागत नहीं किया जा सकता। अयोध्या आने से पहले उन्हें कारसेवकों के परिजनों से माफी मांग कर प्रायश्चित करना चाहिए। संत समाज ने सपा मुखिया के प्रस्तावित दौरे को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह पहले अपना पक्ष स्पष्ट करें। सुभासपा नेता ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सपा मुखिया अयोध्या, मथुरा काशी तो गए लेकिन कभी प्रभु श्रीराम, काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण के दर्शन तक नहीं किए। सपा मुखिया को छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। सपा मुखिया पीडीए पर बहुत बल दे रहे हैं अत: उन्हें यह तथ्य भली भांति पता होना चाहिए कि पीडीए समाज ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जिन रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं उनमें अधिकांशत: पीडीए समाज के ही लोग थे।

सपा के पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीडीए को एक नया अर्थ देते हुए पी को पहले, डी को दर्शन और ए को आशीर्वाद बताते हुए पीडीए अर्थात आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लिखा है। सपा मुखिया द्वारा पीडीए के पारंपरिक राजनीतिक समीकरण को आस्था और दर्शन के साथ जोड़ने की इस रणनीति को पीडीए समाज के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की दृष्टि से देखा जा रहा है। भारी राजनीतिक दबाव पड़ने के बाद सपा मुखिया बयान दे रहे हैं कि 卐भगवान सबके हैं卐 वह अयोध्या, मथुरा, काशी केदारेश्वर सभी जगह जाएंगे। राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि सपा हिंदुत्व की लहर के कारण असहज है। एक ओर सपा मुखिया अयोध्या जाने का ऐलान करते हैं वहीं दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी के डर से जेल में आजम खान से मिलने जाते हैं।

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या आने की बात कही वहीं उनकी प्रमुख सहयोगी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अंग्रेजी समाचार पत्र गार्जियन को दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि जब छह दिसंबर1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो उस दृश्य को टीवी पर देखकर वे खूब रो रही थीं, ऐसा जी जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सपा मुखिया के क्या विचार हैं? छह दिसंबर 1992 की घटना के बाद जिस प्रकार से भयावह दंगे हुए और शहर -शहर कर्फ्यू लगा दिया गया क्या सपा मुखिया अपने पूर्वजों के उन कृत्यों के लिए माफी मांगेंगे?

सपा मुखिया 30 अक्टूबर तथा दो नवम्बर 1990 की घटनाओं पर स्वयं तो चुप हैं किंतु उनके सांसद उस वीभत्स कृत्य पर बयानबाजी कर रहे हैं। सपा सांसद एस.पी. सिंह पटेल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो कदम उठाया था वह बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि जब कारसेवक जबरदस्ती कर रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए सरकार ने गोली चलवाई। सपा सांसद सनातन पांडेय और सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी भी कारसेवकों के नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यही माना जाएगा कि सपा मुखिया निहित राजनैतिक स्वार्थ के लिए अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। सपा मुखिया को लग रहा है कि जनमानस पुरानी घटनाओं को भूल जाता है और मात्र अयोध्या जाकर उनको रिझाया जा सकता है।सपा के शासनकाल में रामभक्तों व सनातन हिंदू समाज पर वीभत्स अत्याचार हुए हैं।

'दिवाली' को 'ईद' जैसा बताने के पीछे असल मंशा क्या है?

अजय बोकिल

भारत में वोटों के लिए राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे दिवाली और ईद को लेकर दिया गया वो बयान है, जो ऊपरी पर धार्मिक सौहार्द की नई इबारत लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपी मंशा कुछ और है। यह सही है कि चाहे दिवाली हो अथवा ईद दोनों ही खुशियों के पर्व हैं, दोनो लंबी प्रतीक्षा के बाद आते हैं, लेकिन दोनों को मनाने के पीछे भावना, तासीर और तरीके अलग-अलग हैं।

जहां ईद महीने भर के कठिन संयम और इबादत के बाद जीवन की सामान्य दिनचर्या में प्रवेश का पर्व है, वहीं दिवाली मूलत: प्रकाश और आनंद का उत्सव है। यानी जी भर, जीयो, खाओ, पीयो, लक्ष्मी मां की आराधना करो और रिश्तों का सम्मान करो। दिवाली मूलत: समृद्धि की आकांक्षा का पर्व है। जबकि ईद के सेलीब्रेशन में भी सादगी का आग्रह निहित है।

दिवाली धन-धान्य, मनुष्य और मवेशियों के आपसी सम्बन्धों को रेखांकित करने वाला त्यौहार भी है, जबकि ईद छोटे-बड़े सभी को गले लगाने का त्यौहार है। दिवाली नई फसल के स्वागत का उत्सव भी है, जबकि ईद का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ईद साल में दो बार मनाई जाती है, लेकिन दोनो के संदर्भ अलग-अलग हैं। जबकि दिवाली साल में एक बार ही आती है। इसका सम्बन्ध साल के नए हिसाब-किताब से भी रहा है। लेकिन ईद खुशियों की साझेदारी के साथ कुर्बानी का भी पर्व है।

दिवाली शब्द दीपोत्सव का बिगड़ा लेकिन ज्यादा प्रचलित शब्द है। दीपोत्सव मनाने के हिंदू सहित चार धर्मों में अलग-



अलग कारण हैं, लेकिन सब में भाव एक-सा है। वह है उल्लास और मंगल कामना का। दीपावली अपने आप में असमाप्त आनंद का पर्व है। यह अकेला त्योहार है, जो पूरे पांच दिनों तक चलता है। इसमें कहीं कोई उपवास नहीं, कहीं कोई वर्जना नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। आपकी हैसियत, आकांक्षा और मर्यादा के हिसाब से दिवाली मनाइए और जीवन में सतत प्रकाश की कामना करते रहिए। दिवाली एक मात्र पर्व है, जिसमें रोशनी के साथ पटाखों की गूंज की जुगलबंदी है। शायद इसलिए क्योंकि दिवाली खुशियों का उत्सव के साथ साथ उसका धमाकेदार सार्वजनिक ऐलान भी है (यह बात अलग है कि इससे पर्यावरण की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं)।

दिवाली धन की देवी की आरती और उसके बारंबार आने की कामना का पर्व है। खरीदारी ईद पर भी होती है। लेकिन दिवाली जैसा आसमान छूता बाजार नहीं चमकता। ईद और दिवाली में साम्य यह है कि इसे सब मिलकर मनाते हैं। ये त्योहार परिवारों और परिचितों को और करीब लाते हैं। दोनों जगह दान और शुभकामनाओं के आदान प्रदान का महत्व है। दोनो में मनोमिलन और दिलदारी का आग्रह है। दोनो त्यौहारों में ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव उसके निरंतर कृपावंत रहने की प्रार्थना निहित है। यह तो हुई दोनों पर्वों की तुलना, धार्मिक और सामाजिक व्याख्या। लेकिन राजनीति इसे अपने नजरिए से देखती और उसकी अलग दृष्टि से व्याख्या करती है। मल्लिकार्जुन खरगे का बयान भी सियासी गुगली ही है। वरना अपने साठ साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने इस तरह से दोनो त्यौहारों की तुलना शायद ही कभी की हो, जिस पर इतना सियासी बवाल मचा है।

गौरतलब है कि दीपावली के पर अपनी बधाई में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- दीपावली की शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूं। ये एक बहुत बड़ा त्योहार हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं। इसका एक ही कारण है कि ये 'खुशियों की एक ईद' है। बहुत दिनों तक चलने वाली ईद यही है। लोगों को सुख-शांति से रहने के लिए और अपने लोगों से मिलने के लिए ये एक अच्छा त्योहार है। मैं अपने देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। खरगे के बयान पर भाजपा तुरंत हमलावर हुई।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खरगे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा- दिवाली के मौके पर भी कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति चुनी। कांग्रेस अध्यक्ष ने दीपावली को खुशियों की ईद कहा। याद कीजिए, सोनिया गांधी बाबरी के लिए रोई थीं। पहले जब सनातन को डेंगू-मलेरिया और एड्स कहा गया, तब कांग्रेस चुप रही।

दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा- खुशी की बात जब आती है तो ईद से मिसाल दी जाती है। अगर मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसी बात कही है, तो यह एक सेक्युलर आदमी ही बोल सकता है।' खरगे के बयान पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिक्रियाएं संतुलित थीं। जबकि केंद्रीय मंत्री और दलित नेता रामदास आठवले ने कहा कि खरगे सीनियर नेता हैं। इसके बावजूद वो दिवाली और ईद को मिक्स करते हैं, ये ठीक नहीं हैं. उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

बहरहाल खरगे जी ने दिवाली और ईद को मिक्स-अप करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया कि वो दिवाली के साथ कौन-सी ईद की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो यह बात ईदुल फितर के संदर्भ में ही कह रहे होंगे। वरना साल में एक बार ईदुज्जुहा भी आती है, जब धार्मिक कारणों से पशु बलि (कुर्बानी) दी जाती है।

आश्चर्य नहीं कि कल को कोई नेता ईदुज्जुहा की तुलना दिवाली के दौरान होने वाली गोवर्धन पूजा के साथ की जाने वाली 'बलि पूजा' से कर दे, क्योंकि दोनो में बलि शब्द है। देखने की बात यह है कि खरगेजी आगामी ईद पर अपनी बधाई किन शब्दों में देते हैं, क्या वो ईद को 'खुशियों की दिवाली' कहने का साहस दिखाएंगे? क्योंकि हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का इससे बेहतर शाब्दिक भाव और सदिच्छा कुछ और नहीं हो सकती।

जाहिर है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वैसे भी उनकी ताजा बधाई का संदर्भ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी है। लिहाजा नए-नए टोटके, व्याख्याएं और प्रतीक खोजे जा रहे हैं। जो दांव चल जाए।

यहां तर्क दिया जा सकता है तो अगर भाजपा हिंदू-मुस्लिम खाई को चौड़ा करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है तो खरगेजी ने 'ईद की खुशी' को 'दिवाली के आनंद' से जोड़ दिया तो क्या गुनाह किया? वैसे भी इन त्योहारों पर हिंदू- मुसलमान एक दूसरे को बधाई तो देते ही हैं।

यू.पी. चुनावों को लेकर प्रियंका की सक्रियता

राहिल नोरा चोपड़ा

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा अपने संगठनात्मक और चुनावी तंत्र को तैयार करने के साथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य के मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका की तलाश कर रही हैं। हाल ही में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसके दौरान उन्होंने पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में यू.पी. कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, यू.पी.सी.सी. कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल हुए।

खबरों के मुताबिक, चर्चाओं में स्क्रीनिंग, अभियान और प्रबंधन पैनल जैसी आवश्यक समितियों के गठन पर जोर दिया गया। जब सीट-बंटवारे की बातचीत औपचारिक रूप से शुरू होगी, तो प्रियंका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बातचीत में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ विपक्ष के राष्ट्रीय अभियान के मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। कांग्रेस नेतृत्व जाति जनगणना की बहस को भी ओ.बी.सी., दलितों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का एक व्यापक गठबंधन बनाने के तरीके के रूप में देखता है। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रियाओंमें कथित अनियमितताओं को लेकर हाल ही में विपक्ष का अभियान, जिसका प्रतीक 'वोट बचाओ, देश बचाओ' नारा है, एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा = 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (ए.आई.एम.आई.एम.) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एक नएगठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की घोषणा की है। हालांकि, ओवैसी ने घोषणा की कि आजाद एस.पी.एम. गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि आजाद ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस से इस नए राजनीतिक गठन में शामिल होने की अपील की। यह कदम आने वाले चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम और दलित आबादी अच्छी-खासी है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी-आजाद गठबंधन सपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा और 2027 के चुनावों में एक चुनौती बनकर उभर पाएगा? सपा का ध्यान दलित वोट साधने पर = 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यू.पी. में दलित वोटों को साधने के लिए, सपा ने रणनीतिक रूप से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा के गढ़ों में दलित सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, ऐसी पहली बैठक 15 नवम्बर को भाजपा का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले आगरा में आयोजित की जाएगी। भाजपा ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आगरा में शिक्षकों की सीट के लिए हाल ही में हुए एम.एल.सी. चुनाव में अपना उम्मीदवार भाजपा को हराने में सफल रहने के बाद पार्टी काफी उत्साहित है।



बच्चे में इस डर को दूर करने की कोशिश कर

आम तौर पर देखा जाये तो नवजात शिशु किसी वजह से डर जाते हैं या घबरा कर उठ जाते हैं। हालाँकि, यह समस्या न केवल नवजात में बल्कि एक साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि उन्हें डर लगता है। ऐसे में अभिभावकों को उन्हें डर से बचाने यह करना होगा।

नवजात शिशु कई बार अचानक से उठ जाते हैं। इतना ही नहीं वह रोना भी शुरू कर देते हैं। वहीं जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनमें भी यह समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वह अपनी कल्पना को नींद के जरिए ही देखते हैं, जिसमें कुछ अच्छे सपने भी होते हैं और कुछ बुरे सपने भी होते हैं।

बच्चे को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से लगता है। कुछ अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को शांत करवाने के लिए या अपनी बातों को मनवाने के लिए अँधेरे का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि, इससे बच्चे काफी डर जाते हैं, जिसका असर बच्चे पर बहुत बुरा होता है। ऐसे में, अपने बच्चे में इस डर को दूर करने की कोशिश करें।

जब बारिस का मौसम होता है, और खासकर जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो बच्चे डर कर उठ जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि इसके आवाज को सुनकर रोने लगते हैं। ऐसे में, आप अपने बच्चे को इसके बारे में बताएं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और उन्हें शांत रखने की कोशिश करें।

हालाँकि, यह सच है कि बच्चे उन लोगों के पास ज्यादा खुशी से रहते हैं, जिन्हें वह जानते हैं पर जैसे ही आप उन्हें अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलाते हैं तो वह बहुत असहज महसूस करते हैं, और कभी-कभी उन्हें देख कर रोने लगते हैं। ऐसे में, आप अपने बच्चे को थोड़ा जानने का समय दें ताकि वह उनके साथ घुल-मिल सके।

बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने अभिभावकों के साथ महसूस करते हैं क्योंकि, वह बचपन से ही उनके साथ रहते हैं, इसलिए जब भी आप अपने बच्चे से थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं तो वह रोने लगते हैं। हालाँकि, यह गलत बात है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ अपनी आदत न लगने दें, इसके लिए आप उन्हें अपने दादा-दादी या फिर घर के अन्य लोगों के साथ छोड़ें। ताकि वह आपके अलावा, घर के अन्य लोगों के साथ घुल-मिल सकें।



खाना खाते समय मोबाइल - टीवी देखने के नुकसान

आजकल माता-पिता के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को मनाकर खाना खिलाने में समय दे पाएं। ऐसे में अधिकतर अभिभावक समय बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद लेते हैं क्योंकि बच्चे मोबाइल या फोन देखते हुए फटाफट खाना खा लेते हैं. यह उनके मन बहलाने की जरूरत बन जाता है। माता-पिता भी इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो फोन या टीवी देखते ही सही, बच्चा खाना तो खा ले रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका यह शॉर्टकट बच्चे की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।



एक रिपोर्ट के अनुसार टीवी या मोबाइल देखते हुए जो बच्चे खाना खाते हैं, वो आगे चलकर भी खाने को लेकर नखरे करते रहते हैं। इन बच्चों में छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करते भी देखा गया है। टीवी-मोबाइल देखते हुए खाने वाले 10 साल तक के बच्चों में मोटापे का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है और वे ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम निर्धारित किया गया है. इन बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम शारीरिक और मानसिक सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इस रिपोर्ट मेंबच्चों को मोबाइल, टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहने की हिदायत दी गयी है।

खाना खाते समय टीवी देखने के नुकसान

1 खाते समय टीवी देखने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे शरीर में फैट जमा होने लगता है।
2 टीवी देखते हुए खाना खाने से सारा ध्यान टीवी या फोन पर होता है, इस वजह से बच्चे ओवरईटिंग करते हैं।
3 ज्यादातर बच्चे जब टीवी-फोन देखते हैं तो उस समय जंक फ़ूड ही खाना पसंद करते है।
4 टीवी-मोबाइल देखते समय डिनर या लंच करने से बच्चे काफी जल्दी से मोटापे के शिकार हो जाते हैं।
5 टीवी या फोन दिखाकर बच्चे को खाना खिलाने से उनके पोषण की कमी हो सकती है। वे जरूरी पोषक तत्व पा नहीं सकते हैं।
6 टीवी या फोन देखकर खाना खाने वाले बच्चे समाजिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं. उनमें स्किल्स में कमी आ सकती है।
7 टीवी-मोबाइल देखते हुए बच्चे बिना बोले खाना खाते हैं, जो उनके बोलने की क्षमता यानी कम्युनिकेशन प्रभावित करता है.
8 आंखों से पानी आने, रोशनी कम होने या ड्राईनेस की समस्या
9 मोबाइल देखने के चक्कर में बच्चों को खाने की पहचान नहीं हो पाती, जो भी सामने आया उसके बारे में बिना जाने ही खा लेते हैं!
10. मोबाइल-टीवी में खोने की वजह से चीजों को याद नहीं रख पाते हैं।

परिवार की धड़कन : रिश्तों की जड़ें मजबूत करते हैं दादा-दादी



आज के समय में जब जीवन बहुत तेज हो गया है और हर कोई अपने काम में व्यस्त है, ऐसे में परिवार के बुजुर्ग यानी दादा-दादी और नाना-नानी केवल रिश्तेदार नहीं होते, बल्कि वे परिवार की असली नींव होते हैं। उनका अनुभव, उनका स्नेह और उनका साथ बच्चों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। वे परिवार में भावनात्मक मजबूती, परंपराओं की निरंतरता और जीवन की समझ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

भावनात्मक सुरक्षा की मजबूत नींव

दादा-दादी और नाना-नानी बच्चों को ऐसा प्यार देते हैं जिसमें कोई शर्त नहीं होती। यह निस्वार्थ प्रेम बच्चों के मन में सुरक्षा और अपनापन पैदा करता है। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें बिना किसी अपेक्षा के समझता और स्वीकार करता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे अपने मन की बातें खुलकर कह पाते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। आज के दौर में जब माता-पिता काम की वजह से अक्सर व्यस्त रहते हैं, तब बुजुर्गों की मौजूदगी बच्चों को स्थिरता और सुकून देती है। उनका शांत स्वभाव और धैर्य बच्चों को मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

अनुभव और सीख का खजाना-बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव होता है। उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए वे बच्चों को धैर्य, सहनशीलता और सही-गलत की समझ सिखा सकते हैं। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं होतीं, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। जब दादा-दादी अपने बचपन या संघर्षों की बातें साझा करते हैं, तो बच्चे जीवन की असली कीमत समझते हैं। इससे उनमें मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता विकसित होती है, जिसे हम मानसिक दृढ़ता या 'रेजिलिएंस' कह सकते हैं।

संस्कार और परंपराओं का संचार- हर परिवार की अपनी परंपराएं और संस्कार होते हैं। इन्हें आगे बढ़ाने में बुजुर्गों की अहम भूमिका होती है। त्योहारों की कहानियां, पारिवारिक रीति-रिवाज, लोकगीत और पारंपरिक व्यंजन ये सब बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ते हैं। बुजुर्ग बच्चों को यह सिखाते हैं कि परिवार और समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इससे बच्चों में सम्मान, करुणा और सहानुभूति जैसे गुण विकसित होते हैं।

संवाद और समझ का सुरक्षित स्थान - अक्सर बच्चे अपने माता-पिता से कुछ बातें कहने में झिझकते हैं, लेकिन वे अपने दादा-दादी या नाना-नानी से आसानी से दिल की बात साझा कर लेते हैं। बुजुर्ग ध्यान से सुनते हैं, बिना डांटे या दबाव डाले समझाने की कोशिश करते हैं। उनका यह व्यवहार बच्चों में आत्म-सम्मान और भरोसा बढ़ाता है। बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनकी भावनाएँ महत्वपूर्ण हैं और उन्हें समझा जा रहा है।

बदलती दुनिया में स्थिरता का सहारा- आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई का दबाव और तकनीक का बढ़ता प्रभाव बच्चों पर मानसिक दबाव डालता है। ऐसे समय में दादा-दादी और नाना-नानी एक शांत और सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं। उनका स्नेह और मार्गदर्शन बच्चों को तनाव से बाहर निकलने में मदद करता है। वे बच्चों को यह सिखाते हैं कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। परिवार में बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े लोग नहीं होते, बल्कि वे भावनात्मक मजबूती, संस्कार और अनुभव के स्तंभ होते हैं। उनकी मौजूदगी से बच्चों को आत्मविश्वास, प्यार और जीवन की सही दिशा मिलती है।



बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं मधुमेह के मामले

फलों और हरी सब्जियों की कमी से शिकार हो रहे बच्चे

बच्चों में मधुमेह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जानकारों के अनुसार फलों और हरी सब्जियों की कमी से मधुमेह (डायबिटीज) का रोग बढ़ा है। 10 या 11 साल की की उम्र में ज्यादातर बच्चें अधिक वजन वाले या मोटापे का शिकार हो रहे है जिससे उनमें डायबिटीज जैसी बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि हर दिन दो तिहाई से अधिक लोग फलों और हरी सब्जियों का खाने में कम इस्तेमाल करते है, जिससे उनमें डायबिटीज टाइप 2 जैसी गंभीर बिमारी होने के खतरा हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि व्यस्क हर दिन फलों और सब्जियों के तीन या उससे कम हिस्से का सेवन करते हैं जिससे करीब 12 मिलियन लोग, डायबिटीज टाइप 2 के शिकार हो सकते हैं।

एक सर्वे में पाया गया कि 66 प्रतिशत व्यस्क हर दिन केवल तीन या उससे कम मात्रा में फल और सब्जियां खाते हैं।

जिनमें से 90 प्रतिशत लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हैं। चैरिटी का कहना है कि अगर लोग अपने रहन सहन में बदलाव लाए तो डायबिटीज के पांच मामलों में से तीन से बचा जा सकता है।

हर कोई जानता है कि उन्हें पांच दिन फल और सब्जियां खाना चाहिए लेकिन फिर भी यह सर्वेक्षण बताता है कि यह संदेश लोगों तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रहा है।

यह जानना खतरनाक है कि अधिकांश लोग अभी भी पर्याप्त फलों और सब्जियों के सेवन से काफी दूर हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को इस बारे में भी नहीं पता हैं कि उन्हें कितनी मात्रा में फल और सब्जियां खाना चाहिए। डायबिटीज वाले लोगों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हेल्दी खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिससे उनको इस गंभीर बीमारी को रोकने में आसानी होगी।

लोगों को बंद डिब्बों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में कितनी मात्रा में चीनी पाई जाती है इसकी जानकारी नहीं है। दो तिहाई लोगों को यह नहीं पता कि एक टिन बेक्ड बीन्स में चीनी के पांच चम्मच तक शामिल हो सकते हैं।

लगभग दस में से छह लोगों ने कहा कि वे ज्यादा सब्जियां खाना चाहते है, लेकिन 23 प्रतिशत का कहना है कि वे काफी महंगी होती हैजबकि 10 लोगों में से लगभग एक का कहना हैं कि इसे बनाने में बहुत समय लगता है।

बच्चों के टिफिन में न दे ये चीजें



अगर आप भी अपने बच्चों को लंच में रोज आलू का पराठा या सैंडविच-पास्ता देकर उसके पोषण का ध्यान रख रही हैं तो आप गलत हैं। बच्चों के विकास के लिए स्कूल लंच में इन चीजों को न दें। इससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है।

आलू पराठा- सुबह नाश्ते में अधिकतर परिवारों में आलू का पराठा बनाकर खाया जाता है। आलू का पराठा पेट तो भर देता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर होता है। जिससे बच्चों में फाइबर और प्रोटीन की कमी पैदा हो सकती है। इसके अलावा यह पचाने में भी भारी होता है, जिससे बच्चे सुस्ती महसूस कर सकते हैं।

सैंडविच - सैंडविच बनाने के लिए जरूरी चीजों में सफेद ब्रेड, मक्खन, आलू और चीज की जरूरत पड़ती है। जो पोषण की कमी पैदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद ब्रेड, जिसे मैदा से बनाया जाता है, में फाइबर की कमी होती है। जो बच्चों के बार-बार भूख लगने और मोटापे का कारण बन सकता है।

मीठे स्नैक्स - चॉकलेट, कैंडी, कुकीज, केक, मिठाइयां जैसी चीजें स्कूल लंच में पैक करके ना दें। इस तरह की चीजों में चीनी की मात्रा अधिक होने से दांतों की सड़न और एनर्जी लेवल लो हो सकता है। जिससे बच्चे को जल्दी थकान महसूस हो सकती है।

मसालेदार खाना - बच्चे के लंच में स्पाइसी फूड जैसे मसालेदार चटनी, तीखी सब्जियां, मिर्ची वाले स्नैक्स भी पैक ना करें। जरूरत से ज्यादा मसाले बच्चों के पेट को नुकसान पहुंचाकर उनके लिए स्कूल में असुविधा पैदा कर सकते हैं।

मैगी - मैगी या इंस्टेंट नूडल्स के लिए प्यार, बच्चों से लेकर बड़ों में भी देखा जा सकता है। लेकिन सुबह की पहली मील में मैगी का सेवन, सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव, सोडियम और मैदा बच्चों के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

संसद सत्र बाधित करने राहुल ने लगाया फोन टैपिंग का आरोप

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा फोन टैपिंग का आरोप लगाया जाना संसद के आगामी सत्र को बाधित करने की एक रणनीति है।



लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी पर ऐसे आरोप लगाने का एक सिलसिला कायम करने का आरोप लगाया, जिन्हें वह न तो प्रमाणित करते हैं और न ही उनकी पुष्टि करते हैं। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के ताजा आरोपों के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी से जिम्मेदारी के साथ बोलने और व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन वह हमेशा आरोप लगाकर भाग जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपने लगाए गए आरोपों को प्रमाणित या पुष्ट करने की परवाह नहीं की है। हाजीपुर के सांसद ने गांधी के वोट चोरी के आरोप को लेकर भी उन पर निशाना साधा।

फोन टैपिंग के आरोप पर शाइना एनसी का सवाल

मुंबई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से फोन टैपिंग के लगाए गए आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने शनिवार को राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन क्यों टैप करवाएंगे? उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने और उनके खिलाफ नकारात्मक छवि पेश करने का भी आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने शाइना एनसी और भाजपा पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत में शाइना एनसी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी का फोन क्यों टैप करेंगे? मुझे बताइए, क्या वह कोई गुप्त एजेंट हैं? क्या उनके पास कोई गोपनीय जानकारी है? अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं तो पहले मोदी फोबिया से बाहर आइए।



एनसीपी के विलय की अटकलों पर संजय राउत ने कसा तंज

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले के विलय की चर्चाओं को खारिज करने के बाद राउत ने भी इसी तरह का रुख अपनाया। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली एनसीपी है, जबकि दूसरा गुट अमित शाह की पार्टी का हिस्सा है। राउत ने कहा कि विलय का यह पूरा ड्रामा शाम तक खत्म हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा, दोनों एनसीपी के बीच विलय का खेल चल रहा है। असल में एक ही असली एनसीपी है, जिसका नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं। दूसरा गुट अमित शाह की पार्टी का है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले अमित शाह की एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। राउत ने कहा कि एक गुट सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि दूसरा सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है।



अभिषेक की बढ़ीं मुश्किलें? कोलकाता पुलिस का समन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी ममता गुट) के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोलकाता पुलिस ने उन्हें एक नए मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, यह मामला 31 अक्तूबर को गिरिश पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एक नई एफआईआर से जुड़ा है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि गिरिश पार्क थाने की ओर से अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया है। इसमें उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई 31 अक्तूबर को गिरीश पार्क थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद ने एक सार्वजनिक मंच से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की थीं, जो पुलिस के कामकाज में बाधा डालने और उन्हें धमकी देने की श्रेणी में आती हैं।



अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर संतों में तकरार

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या यात्रा से पहले जहां, संतों का एक वर्ग चाहता है कि अखिलेश, कारसेवकों पर अतीत में की गयी गोलीबारी के लिये माफी मांगें, तो वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि माफी उनके पिता मुलायम सिंह को मांगनी चाहिए थी। वर्ष 1990 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और सहायक संगठनों के आह्वान पर अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल की ओर कूच किए हजारों कारसेवकों पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस घटना के बाद विहिप ने मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए यादव को 'मुल्ला मुलायम' कहा था। भाजपा ने सपा पर निशाना साधने के लिए अक्सर यह मुद्दा उठाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सपा पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। महंत कमल नयन दास ने मीडिया से कहा, हम उनकी (अखिलेश) अयोध्या यात्रा विरोध करेंगे क्योंकि यह कॉस्मेटिक है। वहीं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने इसे सनातन के मानने वालों के लिए गर्व का मामला बताते हुए कहा, जो कभी जाली टोपी के प्रबल समर्थक थे, वे अब मजबूरी में सनातन धर्म को अपनाने के लिए बाध्य हैं।

मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े एलान

अग्निवीरों को 20% आरक्षण शहीद के परिवार को 50 लाख

मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं का ब्योरा दिया। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों की चिंता करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए। वर्दीधारियों का सम्मान डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। उनके अनुसार, अब तक 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 में शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था



भी लागू की गई।

मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।

सीएम ने कहा कि सेना के अनुशासन और प्रशिक्षण से तपकर आने वाले नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की ताकत बनेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी प्रदेश के विकास में उपयोगी बताया।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2021 में समूह ख के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वहीं, सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूर्व सैनिकों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी प्रदेश सरकार की ओर से मासिक पेंशन दी जा रही है।

उमर अब्दुल्ला सरकार में बगावत के सुर तेज

एनसी विधायक ने डिप्टी सीएम को कहा ठग

श्रीनगर। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के भीतर नाराजगी की खबर आ रही थी। यह दरार उस समय और गहरी हो गई, जब पार्टी के विधायक जाविद इकबाल चौधरी ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को ठग कह दिया। जाविद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, उपमुख्यमंत्री एक ठग हैं और वह इस लायक नहीं हैं कि मैं उनके कार्यक्रमों में शामिल होऊं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान और मेरे लोगों के हित सबसे पहले हैं।

यह घटनाक्रम उस बैठक के एक हफ्ते बाद सामने आया है, जो 6 नवंबर को जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी। पार्टी में बगावत को शांत करने के लिए यह बैठक बंद कमरे में 15 नाराज विधायकों के साथ की गई थी। इन विधायकों ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी एवं सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने की मांग की थी।

मीडिया से बात करते हुए बुधल के विधायक जाविद इकबाल चौधरी ने कहा कि हज यात्रा के संबंध में शुक्रवार को जम्मू स्थित राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी पहले से बैठक तय



थी। जाविद इकबाल को हाल ही में जम्मू-कश्मीर हज कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर के जरिए उपराज्यपाल से मेरी मुलाकात को उजागर किया गया और इसकी तुलना उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मेरे शामिल न होने से की गई। इसके जवाब में मैंने उपमुख्यमंत्री को ठग कहा। मैं अपने शब्दों और टिप्पणी पर कायम हूं।

6 नवंबर को मुख्यमंत्री उमर और फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई बैठक के बारे में जाविद ने कहा, उन्होंने (उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी) अपने विधानसभा क्षेत्र नौशेरा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने राजौरी और पुंछ के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हमने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इसकी शिकायत की और उनसे सड़क एवं भवन विभाग वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री ने हमें 15 दिनों के भीतर विभाग बदलने का आश्वासन दिया है।

गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है भाजपा: राहुल गांधी

हैदराबाद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान वह एक गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी बाइक रैली में शामिल हुए। हैदराबाद में आयोजित यह बाइक रैली शिल्पाकला वेदिका से शुरू हुई। राहुल गांधी ने नोवोटेल के पास गिग वर्कर्स को संबोधित किया। वह भारत समिट 2026 में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात हैदराबाद पहुंचे थे और नोवोटेल होटल में ठहरे हुए थे। हैदराबाद पहुंचने पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अन्य मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया।

रैली में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले नोवोटेल होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हाई-प्रोफाइल सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत डॉग स्क्वॉड ने पूरे इलाके की जांच की। इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी गई।

हैदराबाद के हाइटेक सिटी स्थित जयभेरी ग्राउंड में राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है।

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ बैठक की थी, जहां उन्होंने अपनी परेशानियां और दर्द साझा किया था। उस समय उन्होंने गिग वर्कर्स से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम उनकी मांगों पर जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही उनकी मदद करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि



आज कांग्रेस पार्टी अपने उसी वादे को पूरा कर रही है।

तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी डेटा का युग है। आज देशभर में डेटा की चर्चा हो रही है और डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप और उबर जैसी कंपनियां डेटा के आधार पर काम कर रही हैं, लेकिन अब तक भारत में गिग वर्कर्स को अपने ही डेटा तक पहुंच नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि नया कानून गिग वर्कर्स को अपने डेटा पर अधिकार देगा। तेलंगाना सरकार उन्हें यह गारंटी दे रही है कि उनके द्वारा किए गए काम, पूरी की गई राइड और उसके बदले मिलने वाले भुगतान का पूरा ब्योरा उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगा। तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम के शुभारंभ के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स तेलंगाना के शहरों में तेज धूप के बीच सामान की डिलीवरी करते हैं, लेकिन उनके पास आराम करने के लिए कोई निर्धारित जगह नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार हैदराबाद समेत राज्य के सभी शहरों में वाई-फाई सुविधाओं से लैस रेस्ट जोन स्थापित करेगी। इन केंद्रों पर गिग वर्कर्स अपने वाहन पार्क कर सकेंगे और बैठकर आराम करने के साथ जरूरत पड़ने पर सो भी सकेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम वनडे मैच आज

माउंट मोनगानुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम वनडे मुकाबला रविवार को माउंट मोनगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है और उसके पास सीरीज जीतने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड की नजर मुकाबला जीतकर सीरीज बराबर करने पर होगी।



न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 89 रन पर सिमटने के बाद भारतीय टीम अब आखिरी मुकाबले में सम्मान बचाने और सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय बल्लेबाजों के सामने स्विंग और सीम लेती गेंदों की बड़ी चुनौती होगी। पांच मैचों की इस सीरीज में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर अब तक अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। चौथे वनडे में रोहित मैट हेनरी की शानदार गेंद पर चकमा खाकर स्लिप में कैच दे बैठे। वहीं श्रेयस अय्यर तेज गति से अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कप्तान के रूप में अय्यर का पदार्पण भी निराशाजनक रहा। अब दोनों बल्लेबाज आखिरी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। चौथे वनडे में दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों के पावरप्ले प्रदर्शन में बड़ा अंतर देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने छठे ओवर तक भारत का स्कोर चार विकेट पर नौ रन कर दिया था। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर वैसा दबाव नहीं बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी माना कि दूसरी पारी में गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हो गई थीं। चौथे वनडे में बड़ी जीत हासिल करने के बाद न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। टीम के सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने अर्धशतक लगाकर अपनी फॉर्म दिखाई, जबकि विल यंग ने दो बार कैच छूटने के बाद शानदार शतक जड़ा। न्यूजीलैंड की कोशिश पांचवां वनडे जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने की होगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सोडा ऐश के आयात में 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। भारत में सोडा ऐश के आयात में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जैसे क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखला पर विदेशी निर्भरता बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आयात पर बढ़ती निर्भरता घरेलू विनिर्माण क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों के लिए चुनौती बन सकती है। सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (सी-डीईपी) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूएस) के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की है। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के बाद से भारत में सोडा ऐश का आयात 81.3 फीसदी बढ़ा है। घरेलू उत्पादन की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में देश की कुल मांग का करीब 22 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया गया।

आयशर मोटर्स का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 15% बढ़ा

नई दिल्ली। वाहन विनिर्माता आयशर मोटर्स लिमिटेड का चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 1,573 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 1,369 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 20 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 7,422 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 6,172 करोड़ रुपए था। आलोच्य तिमाही में कंपनी का एबिटा (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 16 प्रतिशत बढ़कर 1,760 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 1,512 करोड़ रुपये था।

रेजरपे, सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा को आईपीओ लाने के लिए मंजूरी मिली

नई दिल्ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी रेजरपे सॉफ्टवेयर लिमिटेड और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की स्वतंत्र बिजली उत्पादक कंपनी सेम्बकॉर्प ग्रीन इन्फ्रा को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रेजरपे ने आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष जून में गोपनीय माध्यम से मसौदा दस्तावेज जमा कराए थे। वहीं, सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा ने आईपीओ के जरिए 3,750 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए अगस्त में सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा किए थे। उपलब्ध सूचना के मुताबिक, मसौदा दस्तावेजों की जांच के बाद नियामक ने रेजरपे को तीन नवंबर और सेम्बकॉर्प ग्रीन इंफ्रा को 13 नवंबर को अंतिम टिप्पणियां जारी कीं।

वोडाफोन आइडिया को कर्ज मिलने में अभी समय लगेगा

नई दिल्ली। कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के समूह से कर्ज मिलने में अभी और समय लग सकता है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिजीत किशोर ने यह जानकारी दी। किशोर ने कहा कि कई बैंकों के शामिल होने के कारण कर्ज जुटाने की प्रक्रिया में पिछले अनुमान से अधिक समय लग रहा है। हालांकि, कंपनी को बैंकों के समूह के साथ बातचीत सफल रहने का भरोसा है। वोडाफोन आइडिया के वित्तीय नतीजों पर आयोजित बातचीत के दौरान किशोर ने कहा कि कंपनी को निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों से पर्याप्त वित्तपोषण मिला है, जिससे वह अपने पूंजीगत व्यय की रफ्तार बनाए रख सकती है।

भारत के आर्थिक विकास में राज्यों को बढ़ानी होगी अपनी हिस्सेदारी

प्रहलाद सबनानी

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के समस्त राज्यों को देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। विशेष रूप से उन राज्यों को, जिनकी आर्थिक विकास दर देश की औसत आर्थिक विकास दर से नीचे है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए औसतन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आर्थिक विकास दर हासिल करना आवश्यक है।

वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में गिने जाते हैं। परंतु, 1980 के दशक में इन राज्यों को बीमारु राज्य की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, भारत के 10 में से 4 नागरिक इन राज्यों में निवास करते थे। साथ ही, इन राज्यों की आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी जिससे इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी।

वर्ष 2000-01 में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान 22 प्रतिशत था जो वर्ष 2034-24 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया। पिछले, लगभग 25 वर्षों के दौरान देश के इन चारों बड़े राज्यों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग उसी स्तर पर बना रहा है, जो एक चिन्तनीय विषय होना चाहिए। यदि देश के सबसे बड़े राज्यों का देश के आर्थिक विकास में योगदान नहीं बढ़ेगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में किस प्रकार शामिल हो सकता है। अत: उक्त बड़े चारों राज्यों को अपने आर्थिक विकास को गति देना अब एक आवश्यक आवश्यकता बन गया है।

वर्ष 2024-25 के प्रति व्यक्ति आय (नस्थिक) के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो ध्यान में आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति



आय का स्तर 234,859 रुपए प्रतिवर्ष था। जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 76,000 रुपए प्रतिवर्ष थी, उत्तर प्रदेश में यह 126,304 रुपए थी, मध्य प्रदेश में 170,320 रुपए थी एवं राजस्थान में 206,440 रुपए थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय बिहार में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तीन गुणा अधिक है। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। पूरे भारत में बेरोजगारी की दर 5.1 प्रतिशत है जबकि, राजस्थान में 7.7 प्रतिशत एवं बिहार में 7.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से रोजगार पाने के उद्देश्य से नागरिकों का देश के अन्य प्रदेशों में पलायन 37 प्रतिशत है। अर्थात, पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में होने वाले नागरिकों के पलायन का 37 प्रतिशत हिस्सा केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश का होता है। क्योंकि, इन राज्यों में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित नहीं हो रहे हैं एवं इन प्रदेशों के नागरिक मजबूरी में अन्य राज्यों को पलायन करते हैं ताकि उन्हें अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्त हो सके।

उक्त कारणों के चलते ही, उक्त चारो राज्यों को बीमारु राज्यों की संज्ञा दी गई थी। परंतु, हाल ही के समय में इन राज्यों में, विशेष रूप से, आर्थिक क्षेत्र में, परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उक्त चारों राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारत में कृषि के औसत योगदान की तुलना में, बहुत अधिक है। अर्थात इन राज्यों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 47 प्रतिशत है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत है। प्रदेश की अधिकतम आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है एवं अपने रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अधिक आबादी के कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के चलते प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विकसित नहीं होने के चलते इन क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर निर्मित होते हैं एवं मजबूरी में प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या को कृषि क्षेत्र पर निर्भर होना पड़ता है अथवा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों को पलायन करना होता है। इसी प्रकार, राजस्थान में भी कुल सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, 26 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से एवं 43 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से आता है।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

धरती आबा भगवान
बिरसा मुंडा जी की
जयंती पर शत् शत् नमन





जनजातीय गौरव दिवस





मुख्य अतिथि
श्री नितिन नवीन
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

जनजातीय गौरव दिवस

15 नवंबर 2026 | समय - प्रात: 9 बजे | दशहरा मैदान, धरमजयगढ़ जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

1,544 जनजातीय ग्रामों में 11 विकास गतिविधियों से **56,569** परिवार लाभान्वित

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

6,691 जनजातीय ग्रामों में 25 विकास गतिविधियों से **11 लाख** से अधिक परिवार लाभान्वित

₹60 हजार करोड़
की राशि से जनजातीय क्षेत्रों का उत्थान एवं विकास

महिला उत्थान

महतारी वंदन योजना
19.89 लाख से अधिक जनजातीय महिलाओं के खाते में **₹629.64** करोड़ से अधिक राशि अंतरित

पक्की छत का निर्माण

9.86 लाख जनजातीय परिवारों को मिले पक्के आवास

जनजातीय उत्थान
विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण

वन अधिकार से सशक्तीकरण

4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, **46,868** सामुदायिक वन अधिकार पत्र और **4,412** सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित



श्री विजय शर्मा
माननीय उप मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

श्री अरुण साव
माननीय उप मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

श्री किरण सिंह देव
माननीय प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

#Rajesh

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.